

विधानसभा से पारित निरसन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने जारी की अधिसूचना

92 साल पुराने अंग्रेजी दौर के 7 कानून खत्म, मप्र में अब नहीं होगा इस्तेमाल

नवप्रदेश/भोपाल । मध्य प्रदेश में अंग्रेजी शासन के दौर से चले आ रहे सात पुराने कानून अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। राज्य सरकार ने इन कानूनों को निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून उस दौर में बनाए गए थे, जब मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था और वर्तमान प्रदेश का बड़ा हिस्सा सेंट्रल प्रोविसेज एंड बरार (सीपी एंड बरार) के नाम से जाना जाता था। इन कानूनों में कर्ज के बोझ से दबे लोगों को राहत देने, सूदखोरों से संरक्षण, अकाल राहत कोष, शिक्षा व्यवस्था,

चिकित्सा और भूमि सर्वेक्षण जैसे विषय शामिल थे। इनमें सबसे पुराना कानून 1933 का है, जबकि अंतिम कानून 1947 में लागू हुआ था। यानी करीब नौ दशक से अधिक समय से चले आ रहे इन कानूनों को अब अप्रासंगिक मानते हुए समाप्त कर दिया गया है। अंग्रेजी शासन के दौरान सीपी एंड बरार में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बनाए गए इन कानूनों को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के बाद भी प्रदेश में लागू रखा गया था। समय के साथ कर्ज, जमीन, शिक्षा, चिकित्सा और राजस्व व्यवस्था

से संबंधित कई नए केंद्रीय और राज्य कानून अस्तित्व में आए। इसके बावजूद पुराने कानून तकनीकी रूप से लागू बने हुए थे। केंद्र सरकार की ओर से पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य में लागू पुराने कानूनों की समीक्षा शुरू की। इसी प्रक्रिया में सामने आया कि सीपी एंड बरार के समय के सात कानून अब भी प्रदेश में प्रभावी हैं, जबकि वर्तमान परिस्थितियों में उनका व्यावहारिक उपयोग लगभग समाप्त हो चुका है। अदालतों में लंबित मामलों से भी जुड़ा



था मामला: राज्य सरकार की ओर से इन कानूनों की उपयोगिता का परीक्षण कराया गया। इसमें पाया गया कि कर्ज, भूमि विवाद, शिक्षा और अन्य

संबंधित विषयों पर अब नए और व्यापक कानून लागू हैं। पुराने कानूनों के कई प्राधान्य वर्तमान कानूनी व्यवस्था से अप्रासंगिक हो चुके हैं। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की समीक्षा के बाद सरकार ने इन कानूनों को समाप्त करने का निर्णय लिया। सरकार का मानना ​​था कि पुराने कानूनों के अस्तित्व के कारण कानूनी व्यवस्था में अनावश्यक जटिलता बनी हुई थी और कुछ मामलों में पुराने प्रावधानों के संदर्भ से विवाद लंबे समय तक न्यायालयों में लंबित रहे। गौरतलब है कि सातों कानूनों को समाप्त करने के

लिए राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में निरसन विधेयक पेश किया था। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया। 7 अगस्त को राज्यपाल ने निरसन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके बाद राज्य सरकार ने सातों कानूनों को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। अब इन कानूनों के आधार पर प्रदेश में किसी नए मामले में कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इनके स्थान पर संबंधित विषयों को नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानून और नियम प्रभावी रहेंगे।

कौन-कौन से कानून हुए खत्म-डेट कन्सीलिएशन एक्ट, 1933: सेंट्रल प्रोविसेज एंड बरार के लिए वर्ष 1933 में लागू इस कानून का उद्देश्य कर्ज से जुड़े मामलों और विवादों का समाधान करना था। उस समय ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में कर्ज का बोझ बढ़ी समस्या था। कर्जदारां और लेनदारों के बीच विवादों के निपटारे के लिए इस कानून में व्यवस्था की गई थी। **प्रोटेक्शन ऑफ डेटर्स एक्ट, 1937** यह कानून कर्जदारों को साहूकारों और कर्ज के दबाव से संरक्षण देने के उद्देश्य से बनाया गया था।

आज बेबाक

खड़कसिंह के खड़कने से खिड़कियां खड़कती थीं या नहीं ये तो पता नहीं लेकिन खड़गे जी के खड़कने से खिड़कियां, दरवाजे और रौशनदान सब खड़क जाते हैं। गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष महंमूजुल्लाखान खड़गे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्र गीत वन्देमातरम् के सिर्फ दो अंतरे गाए गए। इस पर खड़गे जी ने कहा कि उन्होंने वही गाया है जो महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक गाते थे। यदि यह अपराध है तो इन सब पर भी कार्रवाई की जाए। इसे ही कहते हैं चित और पट दोनों मेरे और अंटा मेरे बाप का।

राधाकृष्णन 2 को आरंगे रायपुर, दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

रायपुर/नवप्रदेश। देश के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के दो सितंबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव विकास शील ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा, प्रोटोकॉल, यातायात, चिकित्सा, स्वागत और कार्यक्रम स्थल से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन दो सितंबर को रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उनके प्रस्तावित प्रवास को देखते हुए एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल और वहां से वापसी तक की व्यवस्थाओं को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप अंतिम रूप दिया जा रहा है।



गॉल में भारत 600वें टेस्ट में जीता, श्रीलंका 165 रन से हारा, मानव सुथार मैच के हीरो

मानव सुथार ने मैच में 10 विकेट लिए, पंडितकल प्लेयर ऑफ द मैच बने

नई दिल्ली/ए। भारत ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। यह भारत का 600वां टेस्ट मैच था। भारत की जीत के हट्टे 24 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार रहे। उन्होंने श्रीलंका की दूसरी पारी में 6 विकेट सहित मैच में 10 विकेट लिए। देवदत्त पंडितकल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।



सुथार को एक ओवर में 3 विकेट

मैच के पांचवें दिन बुधवार को दूसरी पारी में श्रीलंका का स्कोर 75 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन था। सुथार ने अगले ओवर में तीन विकेट लेकर भारत की जीत लगभग तय कर दी। इस ओवर में सुथार ने सोनल दिनुषा,

प्रभात जयसूर्या और लाहिरु कुमारा को आउट किया। श्रीलंका का स्कोर 9 विकेट पर 199 रन हो गया। सुथार ने अपने अगले ओवर में केशरा गुणुथा को आउट कर श्रीलंका की पारी समेट दी।

सोशल मीडिया को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाएं युवा: हेमंत खण्डेलवाल

नवप्रदेश/भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने बुधवार को भोपाल में 'सोशल मीडिया डायलॉग कॉफी विद स्टेट प्रेसिडेंट' कार्यक्रम में सोशल मीडिया इम्पलूमेंसर्स से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। इसे वाक्य करने में समाज के हर वर्ग और विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। खण्डेलवाल ने कहा कि सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन और सूचना के



आदान-प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों की राय, व्यवहार और सामाजिक दिशा को प्रभावित करने वाला सशक्त प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसलिए सोशल मीडिया इम्पलूमेंसर्स की भूमिका समाज निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। युवाओं को सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्र निर्माण और सकारात्मक बदलाव के लिए करना चाहिए।

विकसित भारत का संदेश जन-जन तक पहुंचाएं: उन्होंने कहा कि एक पोस्ट, वीडियो या रील कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और इसे जनभागीदारी का व्यापक आंदोलन बनाने का प्रयास होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया पर सकारात्मकता, राष्ट्र निर्माण, नवाचार, युवा शक्ति, आत्मनिर्भरता और विकास की सोच को बढ़ावा दिया जाए। देश की उपलब्धियों, युवाओं की सफलता, स्टार्टअप, तकनीक, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए।

बंगाल के न्यू मार्केट होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत

कोलकाता (वार्ता)। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर स्थित 'सिखा इन' होटल तंग कमरों, संकरे रास्तों और बेतरतीब अंदरूनी हिस्सों की वजह से मौत का जाल बन गया है।

न्यू मार्केट इलाके में बुधवार तड़के लगी आग में नौ लोगों की मौत हो गयी। इनमें से ज्यादातर बंगलादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए कोलकाता आए थे। रात करीब 2:30 बजे लगी इस आग ने लोगों को सोते हुए अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शायद एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी



थी। आग लगने के बाद निकलने का कोई सही रास्ता न होने के कारण कई मेहमान बाहर नहीं निकल पाये और दम घुटने से उनकी मौत हो गयी। अधिकारियों को सबसे ज्यादा हैरानी होटल के कामकाज के तरीके को लेकर हुई है। इमारत पुरानी और संकरी थी, जिसमें छह होटल चल रहे थे।

मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी नहीं चला पाएंगे

पहले नोटिस देंगे, तीन महीने में नहीं सीखे तो लाइसेंस रद्द होगा: मंत्री प्रताप मुंबई/ए।

मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी नहीं चला पाएंगे। राज्य में 20 अगस्त से उन ऑटो-रिक्षा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू होगा, जिनके पास मराठी का 'वर्किंग नॉलेज' यानी कामचलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। यह अभियान पूरे राज्य में एक महीने तक चलेगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को इसका ऐलान किया।



आरटीओ की टीमें जांच करेंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ पूरे महाराष्ट्र में इस एक महीने के अभियान की पलाइंग स्वर्ड ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच करेंगी और नए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखेंगी। जांच के दौरान वॉरिंग्टन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

रेल नेटवर्क को बड़ा विस्तार: चार राज्यों में नई लाइनों के लिए 9,450 करोड़ रुपये मंजूर

नई दिल्ली/वार्ता। केंद्र सरकार ने देश के चार प्रमुख राज्यों-पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेल संपर्क को मजबूत करने और पटरियों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक बड़े फैसले को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 9,450 करोड़ रुपये की लागत वाली चार महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।



प्रमुख परियोजनाएं और मार्ग **खड़गपुर-भद्रक (रानीताल)** चौथी लाइन: 173 किलोमीटर लंबी यह लाइन पश्चिम बंगाल और ओडिशा को जोड़ेगी। **भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन:** ओडिशा में 75 किलोमीटर लंबी नई लाइन। **गुमिडीपुडी-गुड्डूर तीसरी एवं चौथी लाइन:** आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच 90 किलोमीटर का महत्वपूर्ण गलियारा।

पीएम गति शक्ति योजना का हिस्सा यह सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के तहत तैयार की जा रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को गति देना है।

लाड़ली बहनों को राखी के शगुन के साथ मिली लाड़ली बहना योजना की राशि

बहनों का सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

नवप्रदेश/भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बहन-बेटियां हमारे घर-आंगन की रौनक हैं। बहन-बेटियों का मान-सम्मान और इनका आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।



उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार हर महीने बहनों से उनकी रक्षा का वादा पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी लाड़ली बहनों को हर महीने सीगात मिल रही है। उन्होंने कहा कि शारदा मां के आशीर्वाद से मैहर अद्भुत होंगी है। बुंदेलखंड की वीरता के प्रतीक आल्हा-ऊदल मां शारदा के

अनन्य भक्त हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में उदारता और रिश्तों का सम्मान करने की परम्परा है। हम भारतीय परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम् अनुसार पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमने आज ही मैहर से प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को नैहर की नेम (राज्य सरकार का उपहार) दिया गया है।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मैहर में हुए राज्यस्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर में मां शारदा भवानी के दर्शन किए। इसके बाद इसी जिले की प्रतिभावान होंगी रिहलाड़ी सुअनन्या अर्वाधिया और सुज्जति पांडे के साथ प्रदेश की

1 करोड़ 25 लाख 13 हजार से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किश्त और रक्षाबंधन के विशेष शगुन के 250 रूपए (कुल 1750 रूपए) के रूप में 2 हजार 148 करोड़ रूपए सिंगल क्लिक से बैंक खातों में अंतरित किये। जून 2023 में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत से अगस्त 2026 तक 39 किश्तों में लाड़ली बहनों के खातों में 63 हजार 248 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा

गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारतीय सेना बहनों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए सशक्त बनी है। रक्षाबंधन का धागा भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है। राज्य सरकार बहनों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करती है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत हर माह बहनों का राशि भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर जिले में लगभग 256 करोड़ रूपए से अधिक की लागत के 25 विकास कार्य का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।



भोपाल नगर निगम: टैक्स से मास्टर प्लान तक घमासान

भवन किराए पर देने का प्रस्ताव पास, पानी-सड़कों पर भी हंगामा

भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में टैक्स, मास्टर प्लान, व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क और निगम भवन किराए पर देने को लेकर पार्षदों ने मास्टर प्लान की मांग पर आसंदी घेरी। पेयजल, जलभराव, सड़क, सफाई और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए।

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल नगर निगम परिषद की बुधवार को हुई बैठक में टैक्स, मास्टर प्लान, व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क, पेयजल, सड़क, जलभराव, सफाई और निगम की संपत्तियों को किराए पर देने समेत कई मुद्दों पर जमकर बहस हुई। कांग्रेस पार्षदों ने मास्टर प्लान लागू करने की मांग को लेकर परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की आसंदी घेरी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान आयुक्त संस्कृति

जैन की गैरमौजूदगी पर अध्यक्ष नाराज हो गए।

मास्टर प्लान लागू करने की मांग पर कांग्रेस ने घेरी आसंदी

भोपाल का मास्टर प्लान लागू करने से लिया गया कर वापस किया जाएगा या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने मास्टर प्लान का प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजने की मांग की।

व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क वापस लेने की मांग

व्यापारियों से वसूले जा रहे व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क का मामला भी सदन में उठा। शबिस्ता जकी ने कहा

परिक्षेत्र बदलने से टैक्स बढ़ने पर सवाल

बैठक शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने संपत्ति कर बढ़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने महापौर मालती राय के मार्च में पेश किए गए बजट भाषण का हवाला देते हुए कहा कि उस समय शहरवासियों पर कोई नया कर नहीं बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके बाद कई इलाकों के परिक्षेत्र बदल दिए गए, जिससे लोगों पर कर का बोझ बढ़ा। महापौर मालती राय ने कहा कि परिक्षेत्र में बदलाव हर साल की प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं और इस बार भी नियमावलीबद्ध बदलाव हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जकी ने सवाल किया कि अगर यह नियमित प्रक्रिया है तो बजट भाषण में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि शहरवासियों पर अतिरिक्त बोझ डालने से पहले परिषद के सामने पूरी जानकारी रखी जानी चाहिए। परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि यह मुद्दा बजट पर चर्चा के दौरान उठाया जाना चाहिए था। जकी ने जवाब दिया कि बजट की जानकारी बैठक से कुछ मिनट पहले मिलती है, ऐसे में पार्षद पहले से तैयारी कैसे कर सकते हैं।

पेयजल टंकियों की सफाई पर हंगामा

कांग्रेस पार्षद नसीम गफूर ने 85 वार्डों की पेयजल टंकियों की सफाई पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि टंकियां कब बनीं और उनकी सफाई कब-कब कराई गई। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में गंदे पानी की शिकायतें आ रही हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो भोपाल में भी इंदौर के भागीरथपुरा जैसी स्थिति बन सकती है। एमआईसी सदस्य रविंद्र राठी ने डीबी मॉल के सामने स्थित पेयजल टंकी की तस्वीरें सदन में दिखाईं। उन्होंने कहा कि किसी भी टंकी की जांच कराई जा सकती है और यदि उनकी बात गलत साबित होती है तो उनके खिलाफ कार्यवाई की जाए।इस दौरान दोनों पक्षों के पार्षदों में तीखी बहस हुई। नसीम गफूर ने दावा किया कि संबंधित टंकी की सफाई उसी दिन कराई गई है। वरिष्ठ पार्षद मोहम्मद सरवर ने कहा कि सिर्फ टंकी की सफाई नहीं, पानी की जांच भी जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि हर टंकी की सफाई की तारीख भी वहीं लिखी जाए।

लेकर पार्षदों ने आपत्ति जताई। इस पर अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी नाराज हुए। उन्होंने सदन की मर्यादा का हवाला देते हुए अधिकारियों को भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होने की चेतावनी दी।

एमआईसी सदस्य बोलीं- अधिकारी मुझे भी जवाब नहीं देते

संबल घोटाले को लेकर पार्षद गुड्डू चौहान ने सवाल किया कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्या अधिकारी-कर्मचारियों पर लोकायुक्त की जांच चल रही है। एमआईसी सदस्य छाया ठाकुर ने कहा कि वह चौहान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एमआईसी सदस्य बने चार साल हो गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उन्हें भी जवाब नहीं देते। जानकारी मांगने पर आरटीआई लगाने को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी मिलने के बाद ही वह सवाल का जवाब देंगी। महापौर मालती राय ने भी उनकी बात से सहमति जताई। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने बाग मुगालिया के अधूरे आवासीय प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। एमआईसी सदस्य छाया ठाकुर ने बताया कि पुरानी ठेका कंपनी ने वर्ष 2019 से 2024 तक काम नहीं किया। उसका

ठेका खत्म कर दिया गया। हितग्राहियों की परेशानी को देखते हुए 12 नंबर क्षेत्र में दो ब्लॉक का काम दूसरे ठेकेदार को दिया गया। जकी ने सवाल किया कि बाग मुगालिया में काम हो रहा है तो उसका भुगतान 12 नंबर क्षेत्र के काम से क्यों किया जा रहा है। उन्होंने इसे लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई। छाया ठाकुर ने कहा कि हितग्राहियों की परेशानी दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

मल्टीलेवल पार्किंग का ठेका बढ़ाने पर सवाल

भाजपा पार्षद आरती अनेजा ने मल्टीलेवल पार्किंग में अख्तर इंटरप्राइजेस का ठेका बढ़ाने पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि ठेका किस नियम के तहत बढ़ाया गया और निर्धारित शर्तों का पालन हुआ या नहीं। उन्होंने संबंधित दस्तावेज भी मांगे। महापौर ने लिखित जवाब दिया। चर्चा के दौरान पार्षद पप्पू विलास घाड़गे ने बीच में हस्तक्षेप किया। इस पर परिषद अध्यक्ष सूर्यवंशी ने उन्हें बीच में बोलने से मना किया। कांग्रेस पार्षद शिरीन खान ने आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्यवाई को लेकर सवाल किया।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का किया निरीक्षण

बांधों एवं जल संरचनाओं में जल भराव की निरंतर करें मॉनिटरिंग : जल संसाधन मंत्री सिलावट

भोपाल/नवप्रदेश। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निर्देश दिए हैं कि समस्त विभागीय बांध, जलाशय तथा अन्य जल संरचनाओं में जल भराव की स्थिति की सतत निगरानी की जाए और इसकी सूचना बाढ़ नियंत्रण कक्ष सहित जिला प्रशासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिदिन दी जाए। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा राउंड द क्लॉक जिलों से संपर्क कर सतत समीक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की हानि से बचा जा सके। बारिश के दौरान पूरा विभागीय अमला पूरी तरह सावधान और चौकस रहे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बोधी कार्यालय भोपाल स्थित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया और

अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री सिलावट ने बांधों में जल भराव एवं इनसे संबंधित गेटों के ऑपरेशन संबंधी जानकारी प्राप्त और समस्त एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य



अभियंता बोधी परियोजना आर. आर. मीणा, मुख्य अभियंता बांध सुरक्षा अरुण सिंह चौहान एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य अभियंता मीणा ने जानकारी दी कि वर्तमान मानसून सीजन में अभी तक 583.40 एम.एम. वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो कि दीर्घावधि औसत की तुलना में 12 प्रतिशत कम है। पूर्वी मध्यप्रदेश में लगभग 14 प्रतिशत कम एवं पश्चिमी मध्यप्रदेश में लगभग 10 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है।

बांधवगढ़ बफर जोन में हरियाली से लगा सैलानियों का मेला जंगल सफारी का आनंद लेने 47 दिनों में जुटे 2 हजार से अधिक पर्यटक

भोपाल/नवप्रदेश। मानसूनी बारिश के साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक निखर उठा है। हरे-भरे जंगल, कल-कल करते झरने जल संरचनाओं में बढ़ा हुआ जल स्तर और खुशनुमा मौसम का आनंद लेने सक्रिय हुए वन्यजीवों की बढ़ी हुई आवाजाही ने पर्यटकों के आकर्षण में कई गुनी बढ़ोतरी कर दी है। मानसूनकाल में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र पर्यटन के लिए बंद है। किंतु पर्यटकों के लिये बफर जोन का हराभरा सौंदर्य भी सफारी का खुला आमंत्रण सिद्ध हो रहा है। बफर जोन की सफारी को लेकर पर्यटकों में उत्साह है। यहाँ 1



जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक 47 दिनों में 400 से अधिक फेरे हुए। इनमें 2 हजार से अधिक पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां बाघिन और उसके शावकों की धमा-चौकड़ी पर्यटकों के लिए सफारी बेनस बन गई है। घने जंगल में शावकों के साथ कई तरह के वन्य जीवों की लुकाछिपी मानसून सफारी को अविस्मरणीय

प्रयोगशाला से निर्माण स्थल तक पहुंचें नवाचार-लोक निर्माण मंत्री सिंह

प्रधानमंत्री के लैब टू लैंड (प्रयोगशाला से धरातल पर लाने) के आह्वान को सार्थक करने हेतु पीडब्ल्यूडी और सीआरआरआई द्वारा कार्यशाला आयोजित

सुरक्षित, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना का निर्माण हमारी प्राथमिकता

तीन तकनीकी सत्रों में नवीन निर्माण तकनीकों, पुनर्रूढ़न और उन्नत कंपोजिट पर हुआ मंथन

भोपाल/नवप्रदेश। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि नवाचार तभी सार्थक है, जब वह प्रयोगशाला से निकलकर वास्तविक निर्माण स्थल तक पहुंचे और मैदानी स्तर पर प्रमाणित परिणाम दे। नवीन तकनीकों को पहले पायलट परियोजनाओं एवं परीक्षण खंडों में परखा जाए तथा सफल परिणाम मिलने के बाद उन्हें व्यापक स्तर पर अपनाया जाए। वैज्ञानिक अनुसंधान केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सीधा लाभ अधोसंरचना परियोजनाओं और आमजन तक पहुंचे। मंत्री सिंह बुधवार को सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर सीएसआईआर-



एएमपीआरआई, भोपाल में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का विषय 'सतत अधोसंरचना के लिए नवोन्मेषी सामग्री एवं उन्नत कंपोजिट' था। इसका संयुक्त आयोजन सीएसआईआर-सीआरआरआई, नई दिल्ली और सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल द्वारा किया गया। मंत्री सिंह ने सड़क एवं परिवहन अधोसंरचना के क्षेत्र में 75 वर्षों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सीएसआईआर-सीआरआरआई को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में

देश के अधोसंरचना क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री का विजन है कि अधोसंरचना का विकास तेज गति से हो, लेकिन निर्माण टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और दीर्घकालिक भी हो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश भी नवीन तकनीकों एवं नवाचारों को अपनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते यातायात, भारी वाहनों, सीमित प्राकृतिक संसाधनों और बदलती जलवायु के बीच हमारा लक्ष्य केवल अधिक सड़कें बनाना नहीं, बल्कि सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल अधोसंरचना विकसित करना

होना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को स्थानीय संसाधनों पर आधारित कम लागत वाली स्वदेशी तकनीकें विकसित करनी होंगी। नई तकनीकें गुणवत्तापूर्ण होने के साथ व्यावहारिक और किफायती भी होनी चाहिए। पराली सहित अनुपयोगी सामग्रियों का अधोसंरचना निर्माण में उपयोग कर पर्यावरणीय समस्याओं को उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। मंत्री सिंह ने कहा कि प्रयोगशालाओं में अच्छे परिणाम देने वाली तकनीकें कई बार अधिक लागत, सामग्री की अनुपलब्धता और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण निर्माण स्थल तक नहीं पहुंच पातीं। वैज्ञानिक संस्थानों, इंजीनियरों और निर्माण एजेंसियों को मिलकर इन बाधाओं का समाधान करना होगा। सीमित संसाधनों में अधिक मजबूत एवं लंबे समय तक चलने वाली सड़कें बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग केवल सड़क, भवन और पुलों का निर्माण नहीं करता, बल्कि इनके माध्यम से नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित एवं बेहतर बनाता है।

भोपाल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन : सीएम हाउस घेरने पहुंचे; पुलिस ने पॉलिटैक्निक चौराहे पर रोका

भोपाल/नवप्रदेश। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नर्सिंग छात्र-छात्राएं बुधवार को भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वे रैली के रूप में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे। इसी बीच पॉलिटैक्निक चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। छात्रों की मांग है कि उन्हें सीएम हाउस जाने दिया जाए, जबकि पुलिस यहां से हटने का कह रही है। शाम 6 बजे तक वे नहीं हटे हैं। छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और न्यायिक प्रक्रिया के कारण उनका भविष्य पिछले करीब छह साल से प्रभावित है। समय पर



परीक्षाएं नहीं होने, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने तथा छात्रवृत्ति में देरी से छात्रों में नाराजगी है। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए B.Sc. Nursing और

GNM के छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया और उसकी वैधता की जिम्मेदारी छात्रों की नहीं है। यदि किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शासन-प्रशासन पर होगी। छात्रों का कहना है कि इसकी सजा विद्यार्थियों को भुगतनी पड़ रही है। इस दौरान मनोज राजक ने बताया कि सरकार से मांग की कि उनकी

समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल ठोस निर्णय लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे केवल मौखिक आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने पर विचार करेंगे। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वे परीक्षा, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। इससे आगे की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांगों में जल्द निर्णय लेकर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बचाने की मांग की।

रियासतकालीन भैरव मंदिर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया वार्षिक जात्रा उत्सव

■ महापौर संजय पांडे,निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन और सुकमा जमींदार परिवार के कुमार जयदेव हुए शामिल

जगदलपुर/नव प्रदेश। पंचायत ब्राह्मणपारा स्थित रियासतकालीन भैरव मंदिर में सावन माह के पावन अवसर पर उत्कल समाज बस्तर संभाग द्वारा वार्षिक जात्रा उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। धार्मिक आयोजन में उत्कल समाज के साथ विभिन्न समाजों के श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में सहभागिता की। सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला चलता रहा। समाज अध्यक्ष राजेश दास ने



बताया कि तीन पंडितों रमेश नंद, आचार्य रोमितराज त्रिपाठी और वीरेंद्र महापात्र ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना संपन्न कराई। इसके साथ ही हवन का आयोजन भी

किया गया,जिसमें श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। आयोजन में महापौर संजय पांडे,निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन और सुकमा जमींदार परिवार के सदस्य कुमार

1936 में महाराज दलपत देव ने कराया था मंदिर का निर्माण

समाज के वरिष्ठ सदस्य श्रीनिवास मिश्रा ने बताया कि भैरव मंदिर ऐतिहासिक और अत्यंत प्राचीन है। वर्ष 1936 में महाराज दलपत देव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तब से उत्कल समाज द्वारा मंदिर की देखरेख की जा रही है। मंदिर में प्रतिदिन विधि-विधान से पूजा-अर्चना भी समाज के लोगों द्वारा की जाती है।

जाता। उन्होंने कहा कि सावन माह के पावन अवसर पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने पूजा-अर्चना के साथ हवन में भी सहभागिता की।

सावन माह में हर वर्ष वार्षिक जात्रा उत्सव का आयोजन

दशकों से चली आ रही इस परंपरा के तहत सावन माह में हर वर्ष वार्षिक जात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं। विभिन्न समाजों की सहभागिता ने आयोजन को धार्मिक सौहार्द,सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का स्वरूप प्रदान किया।

धार्मिक परंपरा और सामाजिक एकता का संदेश

रियासतकाल से चली आ रही भैरव मंदिर की परंपरा को उत्कल समाज द्वारा निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। वार्षिक जात्रा उत्सव में सभी समाजों की सहभागिता ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया।

दस किमी दूर धान बेचने की मजबूरी

घाटधनोरा में खरीदी केंद्र खोलने की मांग

■ इन्द्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति ने केंद्रीय गृहमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर/नव प्रदेश। बस्तर जिले के तोंकापाल तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत घाटधनोरा में नया धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर इन्द्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति ने आवाज बुलंद की है। समिति के संभागीय अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप सहित अन्य पदाधिकारियों ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम बस्तर जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की।

ज्ञापन में बताया गया कि घाटधनोरा में लंबे समय से नया धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इसका कारण घाटधनोरा सहित टिकराधनोरा, मरकापाल, घाटसरीगोपाल, तोतर, छिन्दवहार और कोण्डालुर क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दूरी अधिक होने से किसानों को परिवहन खर्च के साथ समय और



श्रम की भी अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है। समिति ने केंद्रीय गृहमंत्री से किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए घाटधनोरा में नया धान खरीदी उपार्जन केंद्र खोलने की तत्काल स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। ज्ञापन सौंपने वालों में समिति के संभागीय अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

मांग एक नजर में

घाटधनोरा में नया धान खरीदी केंद्र खोलने से आसपास के सात गांवों के किसानों को राहत मिलेगी। वर्तमान में किसानों को लगभग 10 किलोमीटर दूर धान बेचने जाना पड़ता है। समिति ने खरीफ सीजन को देखते हुए केंद्र की स्वीकृति शीघ्र देने की मांग की है। समिति ने कहा कि क्षेत्र में धान उत्पादक किसानों की संख्या को देखते हुए घाटधनोरा में खरीदी केंद्र की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

बस्तर को 80 हजार पौधों की हरित ढाल देने की मांग, इंद्रावती नदी संरक्षण और तटीय कटाव रोकने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

चित्रकोट की गर्जना के बीच कट रही इंद्रावती की धरती

जगदलपुर/नव प्रदेश। चित्रकोट की गर्जना से पहचान रखने वाली इंद्रावती नदी अब अपने ही तटों पर बढ़ते मृदा कटाव के कारण बस्तर की माटी को नुकसान पहुंचा रही है। नदी संरक्षण, तटीय कटाव रोकने और जिले में हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में इंद्रावती बचाओ अभियान,बस्तर-जगदलपुर ने पहल करते हुए कलेक्टर आकाश छिकारा को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। अभियान ने इंद्रावती नदी के दोनों तटों पर करीब 80 हजार पौधे लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है।

अभियान के अनुसार पूर्व में किए गए सर्वेक्षण और चिन्हांकन के आधार पर जिले के पांच जनपद पंचायत क्षेत्रों की करीब 64 ग्राम पंचायतों एवं गांवों में पौधारोपण के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। नदी के दोनों किनारों पर हरित सुरक्षा पट्टी विकसित करने से मृदा कटाव नियंत्रित होने के साथ नदी तटीय जैव विविधता को भी संरक्षण मिलेगा।

अभियान सदस्यों ने कहा कि इंद्रावती बस्तर की जीवरेखा है। तटों पर बढ़ता कटाव,गाद



इंद्रावती संरक्षण के साथ कृषि जैव विविधता पर फोकस

अभियान ने प्रशासन से चिन्हित स्थलों पर प्रस्तावित 80 हजार पौधों के पौधारोपण को प्राथमिकता से स्वीकृति देकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अभियान का कहना है कि इंद्रावती का संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं,बल्कि बस्तर की कृषि,जल सुरक्षा,जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा दायित्व है।

जमाव, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और अन्य मानवीय गतिविधियां नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चुनौती बन रही हैं। ज्ञापन में वर्ष 2020 में प्रकाशित जल आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि वर्षा ऋतु में नदी के एक लीटर पानी में करीब दो ग्राम मिट्टी पाए जाने का उल्लेख तटीय कटाव की गंभीरता को

दर्शाता है। अभियान ने पूरे बस्तर जिले में रिकू एवं अनुपयोगी शासकीय भूमि का सर्वेक्षण कर वहां भी व्यापक पौधारोपण के लिए स्थल चयन की मांग की। अभियान के अनुसार बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के बीच हरित आवरण बढ़ाने से स्थानीय सूक्ष्म जलवायु को संतुलित करने तथा बढ़ते

राग द म्यूजिकल ग्रुप की चौथी वर्षगांठ पर सजी सुरों की यादगार महफिल

जगदलपुर/नवप्रदेश। संगीत, देशभक्ति और बॉलीवुड के सदाबहार गीतों से सजी संगीतमय शाम में राग द म्यूजिकल ग्रुप ने अपनी चौथी वर्षगांठ को यादगार बना दिया। शनिवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित समारोह में कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को दर तक बांधे रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर संजय पांडे एवं पूर्व विधायक रेखचंद जैन रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीतों वंदे मातरम्, ऐ वतन वतन और मिट्टी के बेटे से हुई। इसके बाद -जिया जले-, -ये तूने क्या किया-, -मेरे खेलना सुन-, -दिल का जो हाल है-, -हर किसी को नहीं मिलता-, -ओ साथी चल- और -ये कहाँ आ गए हम- सहित लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुतियों ने माहौल को संगीतमय बना दिया।

सदाबहार गीतों की श्रृंखला में जिंदगी मौत न बन जाए, आंखों में काजल है, कर ले प्यार कर ले, दीवाना मैं हूँ दीवाना, वादा रहा सनम- और बेकार करके हमें-जैसे गीतों ने संगीत प्रेमियों की खूब तालियां बटोरीं। सैक्सोफोन पर देशभक्ति एवं बॉलीवुड की मधुर धुनों की प्रस्तुति भी विशेष आकर्षण रही। सामूहिक प्रस्तुतियों ने समारोह की भव्यता को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम की उद्घोषिका वंदना झा ने प्रभावशाली आवाज और सहज मंच संचालन से पूरे आयोजन में ऊर्जा बनाए रखी। राग द म्यूजिकल ग्रुप के अध्यक्ष बीजू बिस्वास ने कहा कि समूह का उद्देश्य केवल संगीत कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि नई और प्रतिभाशाली गायन प्रतिभाओं को मंच देकर उन्हें अपनी कला निखारने का अवसर देना है।

नारी शक्ति के संकल्प से नशामुक्त और शिक्षित बनेगा यादव समाज

■ प्रदेश स्तरीय सावन उत्सव में महिलाओं ने सामाजिक जागृति का लिया संकल्प

जगदलपुर/नव प्रदेश। सर्व यादव समाज महिला प्रकोष्ठ जिला बस्तर के तत्वावधान में पहली बार प्रदेश स्तरीय सावन उत्सव का आयोजन श्री राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुईं।

मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष धनमती यादव ने कहा कि नारी एवं युवा शक्ति ही समाज को नशामुक्त और शिक्षित बना सकती है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रही है, वहीं समाज शिक्षा के क्षेत्र में भी अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहा है। माताओं को अपने बच्चों को नशे से दूर रखते हुए शिक्षा के प्रति प्रेरित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। खैरगढ़ से



पहुँचीं प्रीति यादव ने कहा कि नारी माँ, बहन, बेटी और बहू के रूप में परिवार की आधारशिला है। महिला शिक्षित होगी तो वह मायके के साथ ससुराल का भी नाम रोशन करेगी। सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में भी महिलाओं को आगे बढ़ने का क़दम है। उर्मिला यादव ने कहा कि समाज में जागृति लाने के लिए महिलाओं को संगठित होकर आगे आना होगा। आपसी मतभेद और वर्गभेद से समाज कमजोर होता है, इसलिए महिलाओं को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

यादव समाज की महिलाएं अब पीछे नहीं रहेंगी: कार्यक्रम संयोजक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बस्तर जैसे वनांचल क्षेत्र में महिलाओं को अपेक्षित सम्मान नहीं मिल पाता,लेकिन प्रदेशभर से महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने साबित कर दिया है कि यादव समाज की महिलाएं अब पीछे नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि सावन उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज की महिलाओं को जोड़ने और उनमें जागृति लाने का माध्यम है।

सावन सोमवार : सांसद महेश कश्यप ने पुष्पवर्षा कर किया स्वागत, महापौर ने कांवड़ियों के चरण धोकर की अगवानी

रामपाल कांवड़ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

जगदलपुर/नव प्रदेश। सावन के तृतीय सोमवार पर श्री श्री लिंगेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति रामपाल के नेतृत्व में महादेव घाट, जगदलपुर से रामपाल तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ियों ने महादेव घाट से पवित्र जल लेकर करीब 16 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की और रामपाल स्थित प्राचीन लिंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पूरे मार्ग में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा।

बस्तर सांसद महेश कश्यप भी शिवभक्तों के साथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने अपने निवास के सामने कांवड़ियों का आत्मीय स्वागत करते हुए जेसीबी से पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। वहीं महापौर संजय



पांडे गोरिया बहार नाला के समीप पहुंचे और रामपाल जा रहे कांवड़ियों के चरण धोकर पूजा-अर्चना के साथ उनका स्वागत किया।

थाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज के संरक्षक कुमार जयदेव ने महादेव घाट में पूजन में शामिल होकर कहा कि रामपाल का प्राचीन लिंगेश्वर महादेव मंदिर बस्तर की धार्मिक एवं ऐतिहासिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र

है। लोकमान्यता के अनुसार भगवान श्रीराम के वनवास काल से इस क्षेत्र का संबंध रहा है। मंदिर की प्राचीनता और परिसर में मौजूद ऐतिहासिक घंटी भी इसके महत्व को दर्शाती है। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष महादेव बघेल, जनपद अध्यक्ष पदलाम नाग, कोषाध्यक्ष मोहन सेठिया सहित समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सेवा-सत्कार से बढ़ा यात्रा का उत्साह

रामपाल मंदिर के मुख्य पुजारी कैलाश ठाकुर ने कहा कि कांवड़ यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी के सहयोग से यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। मार्ग में विभिन्न समाजों,संगठनों एवं समितियों ने कांवड़ियों के लिए पुष्पवर्षा, शीतल पेय,खल्लहार और अन्य सेवा-सुविधाओं की व्यवस्था की। मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, शांति एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।

आस्था का संगम : महादेव घाट से रामपाल तक निकली कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शिवभक्त शामिल हुए। पूरे मार्ग में जयघोष,सेवा-सत्कार और पुष्पवर्षा से श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा। रामपाल पहुंचकर कांवड़ियों ने पवित्र जल से लिंगेश्वर महादेव का अभिषेक किया।

बस्तर के डीएवी स्कूलों के जीर्णोद्धार और खेल

सामग्री की मांग

जगदलपुर/नव प्रदेश। बस्तर संभाग के डीएवी विद्यालयों की जर्जर स्थिति और खेल सुविधाओं की कमी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं रंगाई-पुताई के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि लंबे समय से रखरखाव के अभाव में कई डीएवी स्कूल भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य कराने की मांग की गई है।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

पर निकली मौन मशाल रैली



जगदलपुर/नवप्रदेश। भारत विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले और विस्थापन का दर्श झेलने वाले लाखों लोगों की स्मृति में 14 अगस्त को जगदलपुर में मौन मशाल रैली निकाली गई। नया निगम के आह्वान पर सिरहासार से शुरू हुई रैली कोतावाली चौक पहुंची। हाथों में जलती मशालें थामे बड़ी संख्या में नारवासी,भाजपा कार्यकर्ता और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। गंभीर और भावपूर्ण माहौल में प्रतिभागियों ने मौन रहकर विभाजन पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली में शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राएं, शासकीय

अधिकारी-कर्मचारी,नगर निगम का अमला, युवा और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। रैली के माध्यम से विभाजन के दौरान झेली गई पीड़ा,संघर्ष,त्याग और बलिदान को याद किया गया। प्रतिभागियों ने नई पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी से परिचित कराने और इतिहास से सीख लेने का संदेश दिया। महापौर संजय पांडे ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं,बल्कि उन लाखों लोगों के संघर्ष,पीड़ा, त्याग और बलिदान को नमन करने का दिन है।



सुविचार

यह कभी मत सोचिए कि चार लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? ये वही चार लोग हैं जो आपकी असफलता पर हंसते हैं और सफलता से जलते हैं।

राष्ट्रगीत पर विवाद अनुचित

राष्ट्रगीन वंदे मातरम को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है जो देशहित में नहीं है। सरकार ने जब संसद में कानून बना दिया है कि राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत का गायन भी अनिवार्य है और अब राष्ट्रगीत सिर्फ दो अंतरों तक नहीं गया जाएगा बल्कि पूरे छह अंतरें गाना होगा। राष्ट्रगीत के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा और इसमें किसी भी तरह का व्यवधान डालना राष्ट्रगीत की अवमानना कही जाएगा जिसके लिए तीन साल तक की सजा का प्रावधान है इस विषेयक कानून संसद के इसी मानसून सत्र में पारित हो चुका है। इसके बाद पहली बार इस 15 अगस्त को नई दिल्ली के लालकिले में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूरे छह अंतरें गाने गये थे। देश के अन्य स्थानों पर भी वंदे मातरम के पूरे अंतरों का गायन हुआ था। किन्तु कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में जब वंदे मातरम का गायन हुआ और दो पद गाने के बाद जैसे तीसरे पद का गायन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेई के खिलाफ भी अपराध दर्ज होना चाहिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष खड़गो जी को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उस समय दो अंतरें ही गाने की परंपरा थी लेकिन अब देश की संसद ने इस बारे में नया कानून बना दिया है जो सभी पर लागू होता है। कांग्रेस पार्टी कानून से ऊपर नहीं है। केरल में कांग्रेस की सरकार है और वहां तो इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम का गायन ही नहीं किया गया। वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे भले ही केन्द्र सरकार हमें फांसी पर चढ़ा दें। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी वंदे मातरम को लेकर इसी तरह के विवाददास्पद बयान दिये हैं और भाजपा को खुद पर हमलावर होने का मौका दिया है। नलीजतन यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है जो अनुचित है इसका जल्द से जल्द पटाखे होना चाहिए।

भारतीय चुनाव प्रक्रिया का अमेरिका में डंका

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत जिसकी आबादी 140 करोड़ के भी पार हो चुकी है वहां की चुनाव प्रक्रिया का अब अमेरिका में भी डंका बज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय चुनाव प्रक्रिया के मुरिद बन गये हैं। उन्होंने भारतीय चुनाव प्रक्रिया की मुककेठ से प्रशंसा करते हुए कहा है कि अमेरिका भी भारत जैसी चुनाव प्रक्रिया को अपनाएगा। ट्रंप ने निर्वाचन आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भी तारीफ की है। गौरतलब है कि भारत की विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान लगाती रही हैं। कभी वे अपनी हार का ठिकरा ईवीएम के सिर पर फोड़ती रही हैं तो कभी एमएआईआर को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराती रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी विपक्षी नेताओं ने तरह तरह के आरोप लगाये थे। हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा था तो उन्होंने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा था। जहां भी विपक्षी पार्टियां चुनाव हारती हैं वहां वे पूरी चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं और जहां वे चुनाव जितने में सफल हो जाती हैं वहां वे चुनाव आयोग और ईवीएम पर उंगली नहीं उठाती और चुनावी नतीजों को लोकतंत्र की जीत बताती हैं। उनका यह दोहरा मानदंड ही इस को साबित करता है कि वे अपने पराजय को चुनाव आयोग के मथ्थे मढ़कर अपने समर्थकों को बरगलाते हैं। विपक्ष के इन मगढढत आरोपों को सरकार और चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी नकार चुका है फिर भी वे इससे बाज नहीं आते। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की चुनाव प्रक्रिया को अमेरिका में लागू करने की घोषणा करके विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाया का काम किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब विपक्ष चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर विधवा विलाप करने से बाज आएगा।

आज का इतिहास

नई दिल्ली(वार्ता)। 1828: राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज का पहला सत्र कलकत्ता (अब कोलकाता) में आयोजित। 1897: रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता (अब कोलकाता) के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफ़िलीज मच्छर की पहचान की। 1913: फ्रांस के एडोल्फ़ेगोड पैराशूट के जरिए विमान से उतरने वाले पहले पायलट बने। 1921: केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह की शुरुआत। 1944: राजीव गांधी का जन्म। वह देश के नौवें प्रधानमंत्री बने। 1955: मोरक्को और अल्जीरिया में फ्रांस-विरोधी दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए। 1979: तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 23 दिन बाद इस्तीफा दिया। 1988: पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक का हवाई दुर्घटना में निधन और सीनेट के सभापति गुलाम इश्राक खान राष्ट्रपति बने। 1988: भारत और नेपाल में 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप से एक हजार लोगों की मौत हुई। 1991: उत्तरी यूरोपीय देश इस्तोनिया ने तत्कालीन सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की। 2002: व्षन्तस्तीन छपागमार नेता अबू निदाल मृत पाया गया।



योगेश कुमार गोयल

देश में अक्षय ऊर्जा के विकास और उपयोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ही वर्ष 2004 से हर साल 20 अगस्त को ‘अक्षय ऊर्जा दिवस’ भी मनाया जाता है।

आज न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन है, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। चर्चित पुस्तक ‘प्रदूषण मुक्त संघों’ के अनुसार इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही एक ऐसा बेहवरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह में भी कई चुनौतियां मुंह बाये सामने खड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी-छोटी इकाईयां हैं, जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों का अपार भंडार मौजूद है लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, कुछ साल पहले सौर ऊर्जा के लिए करीब 90 प्रतिशत सौर पैनल विदेशों से आयात किए गए थे, जिससे बिजली



उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई। अब भी भारत की सौर सेल और मॉड्यूल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात से ही पूरा हो रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एएलएमएम नियम और पीएलआई स्कीम के कारण यह निर्भरता घट रही है। 2023-24 में चीन से सौर सेल्स का 53 प्रतिशत और मॉड्यूल्स का 63 प्रतिशत भारत में आया।

देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में अब बढ़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-पावर और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से तथा परमाणु ऊर्जा से भी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा

रहा है। कुल बिजली उत्पादन में अब अक्षय ऊर्जा का हिस्सा अब लगातार बढ़ रहा है, जो भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करता है। भारत में ऊर्जा खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में ऊर्जा की कुल मांग वर्तमान की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी। विशेषकर बिजली तथा ईंधन के रूप में उपभोग की जा रही ऊर्जा की मांग घरेलू एवं कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में ही बिजली तथा पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का लगभग 55 प्रतिशत उपभोग किया जाता है। हम जिस बिजली से अपने घरों, दुकानों या दफ्तरों को रोशन करते हैं, जिस बिजली या पेट्रोलियम इत्यादि ऊर्जा के

एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सुधारों का अगला चरण



शोभा करंदाले

कुछ वर्षों में, एमएसएमई क्षेत्र ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज ‘उद्यम पंजीकरण पोर्टल’ पर 9 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं, जो 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एमएसएमई हमारी आर्थिक में 31त्र तथा निर्यात में 50त्र योगदान देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख भागीदारी है। एमएसएमई भारत के विकास के सूत्रधार हैं। हाल के वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो ‘उद्यम’ पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या से ही स्पष्ट दिखती है, जो 1 अप्रैल 2023 को 1 करोड़ 65 लाख से बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गए हैं।

2. वर्ष 2020 में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण को, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त करके, अधिक व्यापक और समावेशी बनाया गया था। इसके तहत टर्नओवर और निवेश दोनों पर आधारित एक समान मानदंड विकसित किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निवेश सीमा द्वाि गुना बढ़ाकर क्रमशः द्वाि करोड़, पच्चीस करोड़ और एक सौ

पच्चीस करोड़ की गई है एवं टर्नओवर को दो गुना बढ़ाकर क्रमशः दस करोड़, सौ करोड़ और पांच सौ करोड़ किया गया, जिसने इन उद्यमों को पूंजी निवेश बढ़ाने, विकास और तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

वित्त की उपलब्धता एमएसएमई क्षेत्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक ऋा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है और इसके उल्लेखनीय परिणाम दिख रहे हैं। एमएसएमई को प्रदान किया गया ऋा ऋा, वर्ष 2014-15 में 10 लाख करोड़ रुपये था, जो कि अब बढ़कर 38 लाख 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज’ (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋा पर गारंटी उपलब्ध कराता है। इसके जरिए वर्ष 2000 से 2022 के बीच, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दी गई क्रेडिट गारंटी 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये थी, जो पिछले चार वर्षों में अर्थात् 2022-23 से 2025-26 तक बढ़कर 10 लाख 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम



रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अंगर्गत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए एमएसएमई को प्रदान किया गया ऋा से सालाना 25त्र खरीद करना अनिवार्य है; इसमें महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 3त्र और एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4त्र खरीद शामिल है। विगत वर्षों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद में लगातार वृद्धि हुई है। वित्तीय-वर्ष 2020-21 में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सार्वजनिक खरीद का मूल्य 40,717 करोड़ रुपये थे जो कि वित्तीय-वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1,15,801 करोड़ रुपये हो गया है, जो सीपीएसई द्वारा खरीद के लिए लक्षित 25 प्रतिशत की तुलना में 49 प्रतिशत से अधिक है। इसमें

(पीएमईजीपी) के तहत, वित्त वर्ष 2014-15 से अब तक लगभग 8 लाख 34 हजार सूक्ष्म उद्यमों को 24 हजार 903 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है, जिससे अनुमानित 75 लाख लोगों के लिए

एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से 3,984 करोड़ रुपये की खरीद हुई और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली उद्यमों से 9,059 करोड़ रुपये की खरीद हुई है।

एमएसएमई को उनका भुगतान समय पर दिलाने हेतु मंत्रालय ने कई सार्थक प्रयास किए हैं, ट्रेड्स इनमें से एक है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत में एमएसएमई की लिक्विडिटी (नकदी) संबंधी चुनौतियों तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने एमएसएमई क्षेत्र को मार्च 2026 तक 8,71,000 करोड़ रुपये की इन्वॉइस डिसकाउंटिंग के माध्यम से समय पर भुगतान दिलवाया है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जुड़े एमएसएमई की संख्या अप्रैल 2022 में 3,4,430 थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 2,55,000 से अधिक हो गई है। वहीं, एमएसएमई की इन्वॉइस डिसकाउंटिंग की राशि वर्ष 2021-22 में 40,000 करोड़ रुपये से बढ़कर, वित्त वर्ष 2025-26 में 3,47,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। ट्रेड्स पर इन्वॉइस डिसकाउंटिंग का बढ़ता चलन, भारत सरकार के एमएसएमई के समयबद्ध भुगतान के प्रति संकल्प को दर्शाता है।

इसी दिशा में वित्तिात भुगतान और उससे जुड़े विवादों के निपटारे हेतु पूरे देश में 161 सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफ्सी) स्थापित किए गए हैं।

पाठकों की बात		पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया		     		
 स म य तय है, घटना तय है, जो खो रहा है, उससे बेहतर मिलना तय है। जो आज छूट रहा है, उसका अप्सोस कैसा, हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत तय है। कुछ लोग बिछड़ेंगे, कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ रास्ते मुड़ेंगे, मगर मंजिल का मिलना तय है। जो आपका है, वह ढूँढ़ता हुआ आएगा, और जो नहीं है, उसका जाना भी तय है। बस विश्वास रखिए— वक्त अपना काम करेगा, आज नहीं तो कल, हर अधूरी कहानी का पूरा होना तय है।	भारत में होता सदा रिश्तों का सम्मान। मिले अगर जो गाँव का, झूट से देते मान।। झूट से देते मान, रहे चाहे अनजाना। और पूछते हाल, समझकर मामा नाना।। मैलौनी से आप, नात क्यूँ करते गातर। बाल बुद्धि नादान, रीति मत भूलो भारत।।		जंतर-मंतर पर गालीबाज बत्तमीज प्रोटेस्टर्स के समर्थक देख लो बिना गंध मचाए भी जीत हासिल हो जाती है।गर्व है मुझे मेरे झारखंड के संस्कार और संयम पर।पूरी जिम्मेवारी के साथ कहती हूँ छोटे शहरों के बच्चे अभी भी संस्कार बचा कर रखे हुए हैं। जंतर-मंतर पर दिमाग से गंदे और संस्कार से खोखले घरों के बच्चे आए थे।		मोदीजी को गालियाँ देनेवाले ये बताओ मोदी सरकार आने के बाद किस सिलेंडर की लाईन कब लगाई थी पहले कभी सोचे भी थे की गरीबों को घर गैस पैसे भी मिलेगे नही क्योंकि सत्ताधारी ही खाते थे।और इतनी अच्छी रेलगाड़ी सडक हाईवे एयरपोर्ट पोर्ट सोचे थे बनेगे और सबसे बड़ी बात राममंदिर बन गया धारा 370हट गयी पाकिस्तान भिखारी हो गया।	
	- रजनी रामदेव		- प्रीति श्रीवास्तव			
 तु म न कसम क्या दे दी हमें मुस्कुराने की, दुनिया समझ रही है हमें कोई गुम नहीं। परदे जो दिल के खोल दिए, हमने एक बार दुनिया कहेगी ज़ख्म इसे भी तो कम नहीं।	उसके कदमों पर कदम रखकर चलना अच्छ लगता है बहुत प्यार है उससे ,उससे ये कहना अच्छ लगता है लड़ झगड़ लेती हूँ उससे , बिना किसी बात के,, फिर दिन भर उसी को याद करना अच्छ लगता है।		हम सिया के गाँव वाले, हैं युगों से आस पाले। आएगी साकेत से एक दिन,सिया की पालकी। है पता, पाहुन अयोध्या आ गए हैं जीतकर रण। है खबर, अब पूर्ण हो गई है घड़ी वनवास की। सज गये मंडप, तोरण द्वार, मुँडेर पर कबूतर दे रहे संदेश बादल, आसमानों से उतर कर। है घटाए सावनी, संयम बढ़ाती अब धरा की, गोद होगी फिर हरी, नीज गांव में वसुंधरा की। है सगुन स्वीकार रघुवर- को, विदाई के धिया की, गा रही मंगल हवा, पढ़ पाती मेहंदी डाल की।			
- राकेश मिश्रा	- सुभाष राहत	- पीता खुराना	- पंकज कुमार बसंत		- आशुतोष श्रीवास्तव	
- बरेलवी						

राशि फल



पं. देवव्रत शर्मा

मेष : आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। प्रतिस्पर्धियों पर आसानी से विजय पा लेंगे। दिन कार्य क्षेत्र पर भी अनुकूलता से भरा रहेगा पूर्व में किये परिश्रम का फल मिलने लगेगा। **वृष :** आपका आज का दिन मध्यम लाभदायक रहेगा। परिश्रम की अधिकता रहने से थकान अनुभव करेंगे। सरकारी कार्यों में भाग-दौड़ के बाद सफ़ाता मिल ही जायेगी। संतानों पर ध्यान दें। **मिथुन:** आज का दिन भी आपका सामान्य से अधिक उत्तम रहेगा। आपकी मन्त्रतन्त्राशाओ की पूर्ती होने से दिन भर आनंदित रहेंगे। **कर्क:** आज के दिन आपके गलत व्यवहार के कारण स्वयं एवं परिजनों को परेशानी में डाल

सकते है। सेहत भी साथ नहीं देने से वाणी में तीखापन आएगा। परिजनों से दूरी बढ़ेगी। लघु यात्रा होगी। **सिंह:** आज भी परिस्थितयां आपके पक्ष में रहने से लाभ के कई अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में वृद्धि होने से आय बढ़ेगी नविन स्रोत्रों से भी धन लाभ होगा निवेश के लिए दिन अत्यन्त शुभ है। **कन्या:** आज का दिन आप थोड़ा धैर्य धारण करेंगे। व्यापारी वर्ग आज प्रातः काल से ही कार्य में लग जाएंगे लेकिन कार्य क्षेत्र पर मंदी के चलते आज आपका ध्यान मटक सकता है। **तुला:** आज के दिन आपकी इच्छापूर्ति होने वाली है परंतु इसके लिए दृढ़संकल्प शक्ति की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। काल्पनिक दुनिया को छोड़े लाभ-हानि आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करेंगे। **वृश्चिक:** आज का दिन उताए चढ़ाव वाला

रहेगा। सेहत असामान्य होने से शारीरिक दुर्बलता अनुभव होगी। कार्यों को आज बेगन से करना पड़ेगा। **धनु:** आज का दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा परन्तु आज कार्यों के प्रति लापरवाही अधिक करेंगे जिससे बन्ते काम बिगड़ भी सकते है। **मकर:** आज का दिन आपको सुख शांति प्रदान करेगा। दिन के आरम्भ में ख़ालीपन अनुभव करेंगे। समय व्यतीत करले के लिए मनोरंजन के साधन तलाशेंगे इसमें मित्रो का सहयोग मिलेगा। **कुंभ:** आज का दिन पिछले कुछ दिनों से बेहतर रहेगा। शारीरिक स्फूर्ति रहने से कार्यों में उत्साह रहेगा। रुके हुए कार्य थोड़े से प्रयास से पूर्ण होंगे। **मीन:** आज दिन भर स्वास्थ्य नरम रहने से शारीरिक क्षमता कम रहेगी। कार्यों का बोझ बढ़ने से काफी परेशानी अनुभव करेंगे।

QUIZ TIME

- 1960 में भारत में प्रथम एसटीडी लाईन किन शहरों के बीच स्थापित की गई थी?
- श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास स्थान का नाम क्या है ?
- किस राक्षसी ने अपने मुंह का आकार बदलकर हनुमान जी को उस समय परेशान किया था जब वो लंका जाने के लिए समुद्र के उपर उड़ रहे थे?
- शाहजहां के किस पुत्र ने उपनिषद् और भागवद् गीता जैसे ग्रंथों का पर्सियन भाषा में अनुवाद किया था?
- जापानी महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा को क्या कहा जाता है?

उत्तरमाता-
(1) तख्तन और कानपुर के बीच
(2) टेम्पल ट्रीज
(3) सुसा
(4) दारा शिकोह
(5) किमोनो

RamaQuiz

कार्टून

..सेवा करोगे तो मेवा पावोगे

न्यूज ब्रीफ

अखिल भारत हिंदू महासभा का संगठन विस्तार, राहुल सोनी और नितेश ओझा बने जिला उपाध्यक्ष

इन्दौर । अखिल भारत हिंदू महासभा मध्यप्रदेश द्वारा संगठन विस्तार के तहत इंदौर महानगर में नई नियुक्तियां की गई हैं। जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार राहुल सोनी और नितेश ओझा को जिला उपाध्यक्ष, इंदौर महानगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन के मध्यप्रदेश महामंत्री कन्हैयालाल रैकवार की ओर से दोनों पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। पत्र में उनसे संगठन को मजबूत करने, सदस्यता अभियान को गति देने और संगठन की गतिविधियों को इंदौर महानगर में विस्तार देने की अपेक्षा जताई गई है। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष राहुल सोनी और नितेश ओझा ने संगठन नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए दो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाने की बात कही। अखिल भात हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने दोनों नवनियुक्त जिला उपाध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

पौधारोपण के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की

इन्दौर । मां अहिल्या सेवा संस्था मग्र एवं श्रीजी नारी शक्ति एवं शिक्षा विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में गांधी हॉल परिसर में बच्चों के लिए पेंटिंग, स्लोगन लेखन व फैंसी ड्रेस स्पर्धा आयोजित की गई। जिसमें बच्चों ने प्रकृति, पर्यावरण, जल और जंगल संरक्षण का संदेश दिया। मां अहिल्या सेवा संस्था मग्र की डायरेक्टर डॉ. आरती मेहरा के अनुसार सावन, राखी और हरियाली महोत्सव के अवसर पर गांधी हॉल में लगाए गए उत्पादों के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहे। मां अहिल्या सेवा संस्था की उपाध्यक्ष रश्मि बाकीवाला ने बताया कि इस दौरान पेड़ लगाओ, स्वच्छ सुंदर और स्वस्थ हर-भरा इंदौर बनाओ अभियान के तहत बच्चों से दो-दो पौधे लगावाए गए। निशुल्क ड्राइंग, स्लोगन और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को अतिथियों ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी और विशेष अतिथि सीबी रॉकस्टार चित्तन बाकीवाला थे। इस अवसर पर श्रीजी नारी शक्ति एवं विकास समिति की डायरेक्टर श्वेता विभोर जैन, सहसंयोजक एडवोकेट संजय मेहरा और विभोर जैन सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे।

राजीव गांधी की जयंती पर आज सद्भावना दौड़

इन्दौर । पूर्व प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी एवं मध्यप्रदेश राजीव विकास केंद्र द्वारा आज 20 अगस्त को सुबह 8 बजे सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया है। इस दौड़ में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सफेद कार्डे पहनकर शामिल होंगे। शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश राजीव विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्रसिंह यादव के अनुसार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह आयोजन राजीव गांधीजी के विचारों, देश की एकता, भाईचारे और सद्भावना के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह सिर्फ दौड़ नहीं, र्व. राजीव गांधी के विचारों का जनसंकल्प है। यह दौड़ चौधथराम हॉस्पिटल से शुरू होकर राजीव गांधी प्रतिमा स्थल पर समाप्त होगी।

भजनों में गुंजा भक्ति भाव, 23 स्कूलों के 250 विद्यार्थियों ने दी प्रस्तुति

इंदौर। सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स के तत्वावधान में श्री कलांथ मार्केट बैण्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतरविद्यालयीय भोजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए हुई प्रतियोगिता में सीबीएसई से संबद्ध 23 विद्यालयों के करीब 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने भजनों में सुर, ताल, भाव और भक्ति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रीराम सेंटेनियल स्कूल, स्काय हाइट्स एकेडमी, एमजीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल और श्री वेण्णव एकेडमी को बेस्ट परफॉर्मर ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रस्तुतियों का मूल्यांकन महिला तबला वादक संगीता अग्निहोत्री और गायिका सोनाली पौराणिक ने किया। निर्णायकों ने गायन, सुर-ताल, भावाभिव्यक्ति और प्रस्तुति के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम, दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती वंदना से हुआ। विद्यालय के प्राचार्य नवीन मुदगल ने अतिथियों, निर्णायकों, शिक्षकों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को नियम और दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। प्रस्तुतियों के बीच फिलर कार्यक्रम भी हुए। समापन अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष देवेन्द्र नागर, उपाध्यक्ष रवि सिंगी और सचिव मनोष बाहेती ने विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। निर्णायकों को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीशूष गुप्ता, स्वाध्या गौर और अविता चौहान ने किया।

मां शारदा लोक से मैहर में बढेगा धार्मिक पर्यटन, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे : मुख्यमंत्री

मैहर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को विश्वप्रसिद्ध मां शारदा माता मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की।

इस दौरान उन्होंने कहा कि मां शारदा लोक के निर्माण से मैहर में धार्मिक पर्यटन और तीर्थटन को नई गति मिलेगी। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित पवन पांडेय के सालिध्य में मां शारदा का पूजन किया। दर्शन के बाद



मंदिर प्रबंधन एवं जिला प्रशासन की ओर से उन्हें मां शारदा का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। पूजन-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं, दर्शन व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से मंदिर में आने

वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं के संबंध में भी चर्चा की। **धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई गति**– मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैहर मां शारदा की प्रावन नगरी होने के साथ देशभर की श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मां शारदा लोक के निर्माण से यहां धार्मिक पर्यटन और तीर्थटन का विस्तार

होगा। इससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मैहर आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार का सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। होटल, परिवहन, प्रसाद, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं से जुड़े कारोबार में रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ेंगे। इससे मैहर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी

केयर लीवर्स अपने अतीत से नहीं, संकल्प और उपलब्धियों से बनाएं पहचान: मंत्री भूरिया

भोपाल।

मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि बाल देखरेख संस्थाओं से निकलने वाले बच्चे और केयर लीवर्स केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता हैं। सरकार का प्रयास है कि कोई भी बच्चा संरक्षण की व्यवस्था से बाहर निकलने के बाद स्वयं को अकेला न समझे, बल्कि शिक्षा, कौशल, रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता के अवसरों के साथ समाज की मुख्यधारा में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने कहा कि संघर्ष चाहे जितना बड़ा हो, सफलता उससे बड़ी हो सकती है।

मंत्री भूरिया बुधवार को भोपाल स्थित राज्य होटल प्रबंधन संस्थान में मिशन वास्तव्य के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कैटललिट्ट्स फॉर सोशल एक्शन (सीएसए) के सहयोग से आयोजित बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों एवं केयर लीवर्स की एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। मंत्री भूरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश के केयर लीवर्स अपनी मेहनत और प्रतिभा से प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश में भी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना की वंदी में अपने बच्चों को देखकर गवं की अनुभूति होती है। इन युवाओं की उपलब्धियां बताती हैं कि अवसर और सही मार्गदर्शन मिलने पर परिस्थितियां किसी की सफलता की राह नहीं रोक सकतीं।

नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा मंत्री भूरिया ने युवाओं से एकजुट रहने और अपने साथियों की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने

कहा कि जिस युवा को रोजगार का अवसर मिले, वह अपने अन्य साथियों को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करे। आपको रोजगार मिले, यह अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बेहतर होगा कि आप स्वयं दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में पहुंचें।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का बंद रहा है दायरा

मंत्री भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर आने वाले बच्चों और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। योजना को और सरल बनाने तथा उसका दायरा बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे और युवा इसका लाभ प्राप्त कर सकें तथा उन्हें शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर जीवन के लिए आवश्यक सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि मिशन वास्तव्य के माध्यम से शासन की प्रतिबद्धता है कि कोई भी बच्चा केवल संरक्षण तक सीमित न रहे, बल्कि उसे सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता का पूरा अधिकार मिले।

सफल केयर लीवर्स ने साझा किए संघर्ष से सफलता तक के अनुभव

कार्यशाला में बच्चों एवं केयर लीवर्स ने मंत्री भूरिया से कैरियर, मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार एवं जीवन कौशल



जैसे विषयों पर संवाद किया और मार्गदर्शन प्राप्त किया। बाल देखरेख संस्थाओं से निकलकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का सम्मान भी किया गया। कार्यशाला में सफल केयर लीवर्स ने अपने संघर्ष से सफलता तक के अनुभव साझा किए। उनके अनुभवों ने उपस्थित बच्चों और युवाओं को यह संदेश दिया कि जीवन की शुरुआती परिस्थितियां भविष्य का निर्धारण नहीं करतीं, बल्कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही अवसर सफलता की नई राह खोलते हैं।

सफलता की कहानियों के पीछे संघर्ष की गाथा

इस अवसर पर केयर लीवर्स की सफलता की कहानियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया गया। मंत्री भूरिया ने कहा कि यह पुस्तक केवल सफलता की कहानियों का संकलन नहीं है, बल्कि प्रत्येक कहानी के पीछे छिपे संघर्ष, मेहनत और लक्ष्य प्राप्ति के दृढ़ संकल्प की गाथा

सतना।

मध्य प्रदेश के सतना जिले में धान खरीदी की राशि के भुगतान के एवज में 3 प्रतिशत कमीशन मांगने वाले जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक केसी शर्मा को रीवा लोकायुक्त की टीम ने बुधवार को 96 हजार रुपये की रिश्तत लेते रगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई सतना के प्रेमनगर स्थित उनके आवास पर की गई। रिश्तत की रकम बरामद करने के बाद लोकायुक्त टीम आरोपी प्रबंधक को सर्किट हाउस ले गई, जहां उससे पूछताछ के साथ दस्तावेजी कार्रवाई की गई। लोकायुक्त के अनुसार, नागौद स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक

सिद्धार्थ ओझा ने केसी शर्मा पर धान खरीदी की राशि के भुगतान के बदले कुल राशि का 3 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। कमीशन की रकम करीब एक लाख रुपए बताई गई। लगातार रिश्तत की मांग से परेशान होकर सिद्धार्थ ओझा ने रीवा लोकायुक्त एसपी से शिकायत की थी। शिकायत

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के पंचोर से निकलकर हास्य कविता के मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले कवि चेतन चर्चित अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजगढ़ का गौरव बढ़ाने जा रहे हैं। 21 अगस्त को ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित कवि सम्मेलन में वे अपनी हास्य कविताओं और चुटौती व्यंग्य से श्रोताओं को गुदगुदाएंगे। चेतन चर्चित का काव्य सफर पंचोर से शुरू हुआ और देशभर के मंचों तक पहुंचा। वे अब तक देश के विभिन्न शहरों में आयोजित 1000 से अधिक कवि सम्मेलनों में काव्यपाठ कर चुके हैं। हास्य, व्यंग्य और प्रभावी मंचीय प्रस्तुति उनकी खास पहचान बन चुकी है। इससे पहले नेपाल और दुबई में भी वे हिंदी कविता की प्रस्तुतियां दे चुके हैं। टीवी कार्यक्रमों में भी बिखेरा हास्य चेतन चर्चित राष्ट्रीय टेलीविजन के कई चर्चित कार्यक्रमों में अपनी

है। उन्होंने कहा कि इन युवाओं की उपलब्धियां दूसरे बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी।

बच्चों के हुनर को बाजार से जोड़ने पर जोर

कार्यशाला में बच्चों द्वारा तैयार किए गए जूट बैग, कलाकृतियां और अन्य उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। मंत्री भूरिया ने बच्चों के हुनर की सराहना करते हुए इन उत्पादों को बाजार से जोड़ने तथा स्वरोजगार एवं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल कौशल का प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके हुनर को बाजार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम होना चाहिए। कार्यशाला में औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं विभिन्न संस्थाओं के साथ इंटरैक्शिव और रोजगार के अवसरों को लेकर भी संवाद हुआ। कैरियर मार्गदर्शन, भविष्य की कार्ययोजना, मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक आवश्यकताओं पर विशेषज्ञों ने चर्चा की।

सीएसए के साथ विभागीय समन्वय की सराहना

मंत्री भूरिया ने आप्टर केयर सेवाओं के क्षेत्र में सीएसए द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग और सीएसए के बेहतर समन्वय से केयर लीवर्स के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। उन्होंने सीएसए

की सीईओ स्मिता शेट्टी और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्वेता मोदी सहित पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे अपने विभागीय दौरों में केयर लीवर्स से संवाद करती हैं और उनमें आगे बढ़ने तथा अपने लक्ष्य हासिल करने की ऊर्जा और उत्साह देखकर प्रसन्नता होती है।

युवाओं के सशक्त भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मंत्री भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में हर बच्चे की सुरक्षा, हर युवा का सशक्तिकरण और प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। मध्यप्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से केयर लीवर्स के मार्गदर्शन, सहयोग और उच्च भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के निर्वहन और बच्चों एवं युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने युवाओं से अपने सपनों को सीमित नहीं करने, प्रयास जारी रखने और आत्मविश्वास को कभी कमजोर न पड़ने देने का आह्वान किया। महिला एवं बाल विकास आयुक्त निधि निवेदिता ने कहा कि आप्टर केयर केवल आर्थिक सहायता तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाने की एक सतत प्रक्रिया है। बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर आने वाले युवाओं को शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल के क्षेत्र में निरंतर सहयोग उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 96 हजार की रिश्तत लेते जिला सहकारी बैंक मैनेजर गिरफ्तार



सिद्धार्थ ओझा ने केसी शर्मा पर धान खरीदी की राशि के भुगतान के बदले कुल राशि का 3 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। कमीशन की रकम करीब एक लाख रुपए बताई गई। लगातार रिश्तत की मांग से परेशान होकर सिद्धार्थ ओझा ने रीवा लोकायुक्त एसपी से शिकायत की थी। शिकायत

लोकायुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। टीम ने रिश्तत की रकम भी बरामद कर ली। **बैंक और सहकारिता विभाग में मचा हड़कंप:** जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक के रिश्तत लेते पकड़े जाने की खबर से बैंकिंग और सहकारिता विभाग में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त टीम आरोपी को सर्किट हाउस ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। लोकायुक्त अधिकारी धान खरीदी की राशि के भुगतान, कमीशन की मांग और रिश्तत लेन-देन से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रहे हैं।

पंचोर के हास्य कवि चेतन चर्चित 21 अगस्त को ओमान में सुनाएंगे कविताएं

राजगढ़।

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के पंचोर से निकलकर हास्य कविता के मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले कवि चेतन चर्चित अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजगढ़ का गौरव बढ़ाने जा रहे हैं। 21 अगस्त को ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित कवि सम्मेलन में वे अपनी हास्य कविताओं और चुटौती व्यंग्य से श्रोताओं को गुदगुदाएंगे। चेतन चर्चित का काव्य सफर पंचोर से शुरू हुआ और देशभर के मंचों तक पहुंचा। वे अब तक देश के विभिन्न शहरों में आयोजित 1000 से अधिक कवि सम्मेलनों में काव्यपाठ कर चुके हैं। हास्य, व्यंग्य और प्रभावी मंचीय प्रस्तुति उनकी खास पहचान बन चुकी है। इससे पहले नेपाल और दुबई में भी वे हिंदी कविता की प्रस्तुतियां दे चुके हैं। टीवी कार्यक्रमों में भी बिखेरा हास्य चेतन चर्चित राष्ट्रीय टेलीविजन के कई चर्चित कार्यक्रमों में अपनी



प्रतिभा दिखा चुके हैं। वे स्टार प्लस के 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' में शामिल हुए। इसके

बेतवा के उफनते पानी में कूदी 11वीं की छात्रा, 30 फीट ऊंचे पुल से छलांग लगाकर सेल्समैन ने बचाई जान

विदिशा।

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी में आत्मघाती कदम उठाने वाली कक्षा 11वीं की छात्रा की एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर जान बचा ली। रायसेन निवासी विनोद पटेरिया ने छात्रा को नदी में छलांग लगाते देखा तो बिना देर किए करीब 30 फीट ऊंचे पुल से नदी में कूद गए।

उन्होंने लगभग 150 मीटर तक तैकुर छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाला। युवक की बहादुरी की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार रायसेन शहर के निवासी विनोद पटेरिया विदिशा में एक



निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। वे प्रतिदिन रायसेन से विदिशा आना-जाना करते हैं। बुधवार को भी वह ड्यूटी के लिए विदिशा जा रहे थे। रास्ते में सीठिया गांव के पास बेतवा नदी के पुल पर उन्होंने अपना वाहन रोका। बताया गया है कि वह घर की पूजन सामग्री नदी में विसर्जित करने के लिए वहां रुके थे। इसी दौरान उनकी नजर पुल के पास अकेली खड़ी एक छात्रा पर पड़ी। विनोद ने छात्रा को अकेले और संदिग्ध स्थिति में खड़े देखा तो उससे बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने छात्रा से वहां अकेले खड़े होने का कारण पूछा, लेकिन छात्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद उसने अचानक बेतवा नदी में छलांग लगा दी। छात्रा को नदी में कूदते देख विनोद ने तत्काल अपनी जान की परवाह किए बिना पुल से नदी में छलांग लगा दी।

नदी का पानी तेज बहाव में था, इसके बावजूद उन्होंने छात्रा तक पहुंचने के लिए करीब 150 मीटर तक तैकुर उसे अपने कब्जे में लिया। काफी मशकत के बाद वह छात्रा को सुरक्षित नदी से बाहर निकालने में सफल रहे। घटना की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचने के बाद विदिशा कलेक्टर ने विनोद पटेरिया के साहस और मानवीय संवेदना की सराहना की। प्रशासन ने उनकी बहादुरी को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर की ओर से विनोद पटेरिया को 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की गई है। विनोद की तत्परता और साहस ने एक छात्रा की जान बचा ली। घटना ने यह भी दिखाया कि संकट की घड़ी में समय पर उठया गया एक साहसिक कदम किसी की जिंदगी बचाने में निर्णायक साबित हो सकता है।





21वीं सदी के अंत तक बढ़ जाएगा तापमान! उत्तराखंड की कोसी नदी बेसिन में मंडराया खतरा

दुनिया भर के वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं. इसका गंभीर असर पूरे विश्व में दिखाई देने लगा है. आईआईटी रुड़की और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के शोधकर्ताओं ने क्लाइमेट चेंज के कारण उत्तराखंड की कोसी नदी बेसिन में जल सुरक्षा पर बड़े खतरे की चेतावनी दी है. तापमान बढ़ने के साथ भूजल रिचार्ज में गिरावट और सूखे का जोखिम बढ़ सकता है। 1800 के दशक से इंसानी गतिविधियां क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह बनी हुई हैं. 200 करोड़ लोगों को भोजन-पानी देने वाले हिंदूकुश हिमालय से लेकर समुद्र की गहराई तक पृथ्वी गर्म हो रही है. विश्व के सभी पहाड़ पृथ्वी की सतह के लगभग 20ब क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। पहाड़ दुनिया का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या, गंगलों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों



का अधिक इस्तेमाल और अवैज्ञानिक कृषि पद्धति के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, उत्तराखंड में भी जिन ठंडे पहाड़ों पर कभी एसी-कूलर की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां अब लोग तेज गर्मी महसूस कर रहे हैं. मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। आईआईटी रुड़की और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के

शोधकर्ताओं की एक नई स्टडी ने चेतावनी दी है कि क्लाइमेट चेंज के कारण उत्तराखंड की कोसी नदी बेसिन में जल सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहां तापमान बढ़ने, भूजल रिचार्ज में गिरावट और सूखे का जोखिम बढ़ने से क्षेत्र की खेती, पीने के पानी की सप्लाई और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं।

टारगेट किलिंग’ का पाकिस्तानी मास्टरमाइंड बेनकाब

जम्मू। लश्कर-ए-ताइबा के कमांडर मोहम्मद याकूब उर्फ अबू सुमामा ने कश्मीर में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षाकर्मियों और बेगुनाह नागरिकों की टारगेट किलिंग करने के निर्देश दिए थे। एनआईए कोर्ट ने अब उसके खिलाफगैर जमानती वारंट जारी किए हैं। एनआईए के रिकॉर्ड के अनुसार, मोहम्मद याकूब ने अपने कई छ्त्र नाम रखे थे। उसे अबू सुमामा, सुमामा इलियास और वारिस अली के नाम से भी जाना जाता है। वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित चट्टा बख्तावर इलाके में लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर है। उस पर कश्मीर में सक्रिय लश्कर के आतंकवादियों को वित्तीय मदद देने और आतंकी गतिविधियां संचालित करने का आरोप है। जम्मू के स्पेशल जज (एनआईए) प्रेम सागर ने एनआईए के मुख्य जांच अधिकारी, डिटी एसपी अमित शर्मा की उस अजी की मंजूर कर लिया है, जिसमें बीएनएसएस की धारा 75 के तहत इस फ्गर आतंकी कमांडर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी।



यह कार्रवाई एनआईए बनाम मोहम्मद नकीब भट और अन्य मामले में की गई है। यह मामला तब शुरू हुआ जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के पांडच स्थित गुजर टेट के पास नाका चेकिंग के दौरान एक स्थानीय रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल सवार की पहचान फजल हक कॉलोनी (बटपोरा, श्रीनगर) निवासी मोहम्मद नकीब भट के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक चीनी ग्रेनेड और 15 कारगुस बरामद किए गए। वह इन हथियारों और गोला-बारूद को अपने पास रखने की कोई वैध वजह नहीं बता पाया। इसके बाद पुलिस ने जक्फरा पुलिस स्टेशन में यूएपीए की धारा 23, आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धारा 4 के तहत एफ्आईआर दर्ज की।

झारखंड सरकार को दो महीने का अल्टीमेटम

11 जांच नहीं हुई तो फिर रांची में जुटेंगे छात्र

रांची। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने मंगलवार को आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया। इससे एक दिन पहले सोमवार देर शाम देवेंद्रनाथ गुट ने भी अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। अब छात्रों ने राज्य सरकार को मामले की उच्चस्तरीय जांच पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। मंच ने साफकर दिया है कि अगर तय समय में निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हुई, तो छात्र फिर बड़ी संख्या में रांची पहुंचेंगे और इस बार सीबीआई जांच उनकी मुख्य मांग होगी।

‘छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार झुकी’

कोर कमेट्री के छात्रों ने दावा किया कि उनके आंदोलन का असर हुआ है और राज्य सरकार ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से



सरकार को 2 महीने का समय, जांच नहीं हुई तो फिर आंदोलन

जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेट्री की बैठक में आंदोलन को फिलहाल खत्म करने का फैसला लिया गया। छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं, इसलिए उसे मामले की जांच पूरी करने के लिए थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। छात्रों ने कहा कि सरकार को दो महीने के भीतर जेपीएससी-जेएसएससी से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच पूरी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मंच दोबारा बड़ी संख्या में छात्रों को एकजुट करेगा और राजधानी रांची में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उस समय सीबीआई जांच की मांग आंदोलन का मुख्य मुद्दा होगी।

लिया है। छात्रों के मुताबिक, आंदोलन के दबाव के बाद सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द की हैं, जबकि कई अन्य परीक्षाओं की जांच भी चल रही है। छात्रों का कहना है कि जब सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी है, तो उसे निष्पक्ष तरीके से जांच पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी वजह से फिलहाल आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया गया है। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर अलग-अलग गुटों की ओर से आंदोलन किया जा रहा था। सोमवार देर शाम

राजधानी रांची में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन थम गया है। हालांकि मंच ने साफ किया है कि सरकार की कार्रवाई पर उसकी नजर बनी रहेगी और तय समय में जांच पूरी नहीं होने पर छात्र फिर सड़क पर उतरेंगे।

एसआईआर का असर, कई राज्यों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा मतदान प्रतिशत : चुनाव आयोग

नई दिल्ली/ए। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कहा कि एसआईआर (Special Intensive Revision, SIR) जैसे अभियानों की वजह से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद हुए शुरुआती चुनावों की तुलना में कई राज्यों में मतदान प्रतिशत और कुल मतदान संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे अभियानों ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 1951 के चुनाव में मतदान प्रतिशत लगभग 40 फीसदी था,



जो बढ़कर 2026 में रिकॉर्ड 93.70 फीसदी तक पहुंच गया। इसी अवधि में कुल पड़े वोटों की संख्या 76.35 लाख से बढ़कर 6.40 करोड़ हो गई। पुडुचेरी में 1964 में मतदान प्रतिशत लगभग 65-70 फीसदी था, जो 2026 में बढ़कर 91.19 फीसदी हो गया। वहीं कुल मतदान 1.71 लाख से बढ़कर 8.66 लाख तक पहुंच गया। असम में 1951 में मतदान प्रतिशत करीब 50 फीसदी था, जो 2026 में बढ़कर 86.33 फीसदी

हो गया। राज्य में कुल मतदान 23.48 लाख से बढ़कर 2.16 करोड़ हो गया। तमिलनाडु में 1967 में मतदान प्रतिशत लगभग 70 फीसदी था। बीच के वर्षों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन 2026 में यह बढ़कर 86.03 फीसदी पहुंच गया। राज्य में कुल मतदान 1.59 करोड़ से बढ़कर 4.93 करोड़ हो गया।

केरल में वोटों की संख्या 2.16 करोड़ हो गई। बिहार में 1951 में मतदान प्रतिशत करीब 50 फीसदी था, जो धीरे-धीरे बढ़कर 2026 में 67.25 फीसदी तक पहुंच गया। राज्य में मतदाताओं की संख्या 1.02 करोड़ से बढ़कर 5.02 करोड़ हो गई।

पीयूष गोयल अगले हफ्ते जापान दौरे पर, द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर के पार

नई दिल्ली/ए। भारत और जापान के बीच आर्थिक व रणनीतिक रिश्ते लगातार मजबूती पकड़ रहे हैं। दोनों देशों की साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और साझा समृद्धि की समान आकांक्षाओं पर टिकी है। इसी दिशा में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त के बीच जापान की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। **जापानी कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जापानी प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि जापान यात्रा के दौरान वह जापानी सरकार



और उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, ताकि दोनों देशों की विशेष रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी को और मजबूत किया जा सके। **व्यापार और निवेश के आंकड़े उत्साहजनक** गोयल ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। जापान अब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। ये आंकड़े दोनों देशों के

आर्थिक संबंधों की मजबूती और वैश्विक की अपार संभावनाओं को दर्शाते हैं।

राज्यों तक फैल रहा सहयोग

जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर से आए प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति को लेकर मंत्री ने कहा कि भारत-जापान सहयोग अब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राज्यों और क्षेत्रीय स्तर तक फैल चुका है। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य की विशाल आबादी, बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और कुशल कार्यबल जापानी कंपनियों के लिए आकर्षक अवसर पैदा कर रहे हैं।

आर. प्रज्ञानानंदा ने 2026 ग्रैंड चेस टूर फाइनल में पक्की की जगह

नई दिल्ली/ए। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदा ने 2026 ग्रैंड चेस टूर के फइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सिन्कफील्ड कप में एक राउंड बाकी रहते हुए प्रज्ञानानंदा और अमेरिका के वेस्ली सो पांच-पांच अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। 2026 ग्रैंड चेस टूर में कुल छह टूर्नामेंट शामिल हैं। पोलैंड सुपर रैंपिड एंड ब्लिट्ज, रोमानिया सुपरबेट क्लासिक, क्रोएशिया सुपर रैंपिड एंड ब्लिट्ज, सेंट लुइस रैंपिड एंड ब्लिट्ज, सिन्कफील्ड कप और अंत में ग्रैंड चेस टूर फइनल। प्रज्ञानानंदा के शानदार प्रदर्शन में सेंट लुइस रैंपिड एंड ब्लिट्ज प्रतियोगिता की जीत और सिन्कफील्ड कप में लगातार अच्छे प्रदर्शन की अहम भूमिका रही। इन्हीं नतीजों के आधार पर उन्होंने फइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। ग्रैंड चेस टूर के



आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने प्रज्ञानानंदा को बधाई देते हुए कहा कि सिन्कफील्ड कप में एक राउंड बाकी होने के बावजूद उन्होंने 2026 तल्लड़ फइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। हालांकि, वह अभी भी सिन्कफील्ड कप का खिताब जीतने की दौड़ में बने हुए हैं। ग्रैंड चेस टूर फइनल 21 से 28 अगस्त तक सेंट लुइस चेस क्लब में खेला जाएगा। इसमें टूर के शीर्ष चार खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप में खिताब जीतने

सस्ती दवा, महंगा ब्रांड और करोड़ों का खेल: कर्नाटक में 4.91 करोड़ की नकली दवाएं जब्त

बंगलूरु। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (स्वच्छ) के ड्रग एनफोर्समेंट विंग ने जांच अभियान के दौरान 4.91 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की नकली दवाएं जब्त की हैं। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बेंगलुरु दक्षिण जिले के बिदादी स्थित कुरुबाराकरेनाहल्ली के एक फर्महाउस में बिना लाइसेंस दवाओं की पैकेजिंग और रीलेबलिंग का काम चल रहा था। विभागीय टीम को 18 अगस्त को इस अवैध गतिविधि की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सामने आया कि फर्महाउस में दूसरे राज्यों से सस्ती दवाएं मंगाई जाती थीं। इसके बाद



उन्हें नई शीशियों में भरकर ऐसे लेबल लगाए जाते थे, जिससे वे महंगी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और अलायित दवाओं जैसी नजर आए। विभाग के कमिश्नर श्रीनिवास ने कहा कि नकली दवाओं में प्रभावी औषधीय सामग्री नहीं होती या उनमें गलत अथवा हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस काम में

इस्तेमाल किए जा रहे लेबल पर दिए गए स्कैनिंग कोड भी काम नहीं कर रहे थे। नकली दवाएं ऐसे उत्पाद होते हैं, जिन्हें असली ब्रांडेड दवाओं जैसा दिखाकर ग्राहकों को धोखा देने और मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। जब्त किए गए स्टॉक में Cefivagint 2.5 इंजेक्शन की 5,640 शीशियां, 11इड5घट्टइ इंजेक्शन की 1,531 शीशियां, इड्डु1इड्डुइ5 इंजेक्शन की 470 शीशियां और श्वड्डुइडु1इथ की 264 शीशियां शामिल हैं। इसके अलावा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के 30 बॉक्स, पैकेजिंग सामग्री, इंजेक्शन भरने वाली मशीनरी और नकली लेबल भी बरामद किए गए हैं।

‘ऑपरेशन सफेद सागर’ का नेटफ्लिक्स पर धमाल

मुंबई। 1999 के कारगिल युद्ध की कहानी पर आधारित एरियल-एक्शन सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ इन दिनों चर्चा में है। सीरीज में भारतीय वायुसेना के उन अधिकारियों की बहादुरी दिखाई गई है, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ मिलकर काम किया था। अब फ़िल्म ने रिलीज के बाद ओटीटी पर धमाल मचाया हुआ है।

नेटफ्लिक्स पर छाई सीरीज

7 अगस्त को रिलीज हुई यह छह एपिसोड की सीरीज नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 नॉन-रिंग्लिश टीवी लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंच गई है।

नेटफ्लिक्स के मुताबिक, ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ लगातार दो हफ्तों से ग्लोबल टॉप 10 में बनी हुई है। यह सीरीज दुनिया के 40 देशों में टॉप 10 में जगह



बना चुकी है, जबकि 10 देशों में नंबर 1 का स्थान हासिल कर चुकी है।

‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो स्काइज़ की कहानी दिखाई गई है।

सीरीज में भारतीय वायुसेना के जवानों की बहादुरी, उनकी चुनौतियों और उनके परिवारों की भावनात्मक यात्रा को दिखाया गया है। सीरीज को अभिजीत सिंह परमार और कुशल श्रीवास्तव ने बनाया है और इसका निर्देशन ‘असुर’ फेम ओनी सेन ने किया है।



अनूपपुर जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन से भेदभाव क्यों?

आरक्षण सुविधा में कटौती पर भगवा पार्टी ने रेलवे को घेरा, कन्हैया लाल मिश्रा बोले यात्रियों की सुविधा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

नव प्रदेश इन्द्रपाल यादव

अनूपपुर। अनूपपुर रेलवे जंक्शन पर आरक्षण सुविधा के निर्धारित समय को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय गणवाती अर्थात भगवा पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल मिश्रा ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन की कार्यप्रणाली पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा है कि अनूपपुर जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन पर आरक्षण सुविधा का समय सीमित रखना यात्रियों के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की है कि आरक्षण केंद्र का संचालन समय तत्काल बढ़ाकर पूर्व वत अनुसार किया जाए। कन्हैया लाल मिश्रा ने कहा कि अनूपपुर कोई छोटा या सामान्य रेलवे स्टेशन नहीं है। यह शहरोल सभाग का महत्वपूर्ण रेल जंक्शन है, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न शहरों और

राज्यों के लिए यात्रा करते हैं। इसके बावजूद यदि यहां आरक्षण सुविधा महज छः घंटे तक सीमित रखी जाती है और छोटे स्टेशनों पर इससे अधिक आठ घंटे समय तक सुविधा उपलब्ध रहती है, तो यह व्यवस्था अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती है।

छोटे स्टेशनों पर अधिक समय, जंक्शन पर कटौती क्यों?: मिश्रा ने कहा कि रेलवे का मूल उद्देश्य यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में महत्वपूर्ण जंक्शन पर सुविधा बढ़ाने के बजाय आरक्षण का समय कम किया जाना समझ से परे है। नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए आरक्षण केंद्र का सीमित समय बड़ी परेशानी पैदा करता है।



उन्होंने सवाल उठाया कि जब छोटे स्टेशनों पर आरक्षण सुविधा लंबे समय तक संचालित की जा सकती है, तो अनूपपुर जंक्शन पर समय बढ़ाने में

रेलवे प्रशासन को क्या परेशानी है?

पुरानी खबर भी खोल रही रेलवे व्यवस्था की परतें आरक्षण समय में कटौती को लेकर पूर्व में प्रकाशित समाचार में भी अनूपपुर जंक्शन की समस्या सामने आ चुकी है। उपलब्ध समाचार कटिंग में उल्लेख है कि बिलासपुर डिवीजन द्वारा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण समय घटाकर छह घंटे किए जाने तथा छोटे स्टेशनों पर लगातार आठ घंटे तक आरक्षण सुविधा दिए जाने पर सवाल उठे थे। उस समय भी रेलवे से अनूपपुर सहित महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण समय पूर्ववत करने की मांग की गई थी। यानी मामला केवल आज का नहीं है। आरक्षण सुविधा के समय को लेकर लंबे समय से यात्रियों की परेशानी और स्थानीय स्तर पर विरोध सामने आता रहा है। ऐसे में अब रेलवे प्रशासन को यह

सप्ट करना चाहिए कि वर्तमान में अनूपपुर जंक्शन के लिए आरक्षण समय निर्धारित करने का आधार क्या है और यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं की जा रही है। **सीनियर डीसीएम के रवैये पर भी उठाए सवाल:** कन्हैया लाल मिश्रा ने कहा कि बिलासपुर जोन के संबंधित अधिकारियों, विशेषकर वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारियों को इस विषय को केवल प्रशासनिक आदेश मानकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि यात्रियों की वास्तविक परेशानी को समझना चाहिए। स्थानीय स्तर पर संबंधित सीनियर डीसीएम के कथित अडिगल रवैये को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, रेलवे प्रशासन को उनका भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल

नियम लागू करना नहीं, बल्कि नियमों को जनहित के अनुरूप लागू करना भी है। यदि किसी व्यवस्था के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है तो उसकी समीक्षा करना रेलवे की जिम्मेदारी है। 'रेलवे सुविधा बढ़ाए, अनूपपुर को प्रयोगशाला न बनाएं' भगवा पार्टी जिलाध्यक्ष ने कहा कि अनूपपुर जिले की जनता लंबे समय से बेहतर रेल सुविधाओं की मांग करती रही है। ऐसे में आरक्षण केंद्र के समय में कटौती जैसी व्यवस्था यात्रियों की परेशानी को और बढ़ाने वाली है।

इनका कहना है

आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है इसे मैं दिखवाता हूँ।

राकेश रंजन, डीआरएम रेलवे बिलासपुर

पंचायतों को विकसित बनाने पर जोर

वीबी-जी राम जी’ योजना की दी जानकारी



नवप्रदेश/जबलपुर।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से बुधवार को मानस भवन में जिला स्तरीय पंच-सरपंच सम्मेलन आयोजित किया गया। राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना से गांवों में रोजगार के साथ जल संरक्षण, तालाब, सड़क और अन्य अधोसंरचना के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को केंद्र और राज्य सरकार के लिए योजनाएं और राशि स्वीकृत होने के बिनाजूद धातल पर काम दिखाई नहीं देता। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित तंत्र की कथित लापरवाही एवं कमीशनखोरी का खामियाजा आम जनता को भुगतान पड़ रहा है।

का आग्रह किया। जिला पंचायत

सीईओ अभिषेक गहलोत ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार की अवधि अधिकतम 125 दिन होगी और कार्य मांग आधारित होंगे। योजना में 318 तरह के कार्य चार श्रेणियों में रखे गए हैं, जबकि मध्यप्रदेश में फिलहाल 10 कार्यों को अनुमति दी गई है।

125 दिन रोजगार, ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन पर जोर: योजना के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इनमें कंटूर ट्रेच, बाल्डर चेक डैम, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, कूप जल धरण, सोक पिट, बगिया निर्माण, हरित परियोजना, नर्सरी, पशु शेड और सड़क निर्माण शामिल हैं।

बैंक की तिलवारा शाखा के प्रबंधक

से समन्वय कर श्रा प्रकरणों के जल्द

निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने पात्र किसानों से भी अपील

की कि वे बैंक पहुंचकर लंबित

औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करें।

अक्टूबर में फिर खुल सकता है

पोर्टल: ऊर्जा विकास निगम की

ओर से बताया गया कि योजना में नए

पंजीयन के लिए अक्टूबर के जल्द

पोर्टल/लिंक दोबारा खुलने की

संभावना है। इससे नए किसान भी

सोलर कृषि पंप के लिए आवेदन कर

सकेगे। मुलाकात के दौरान भारत

कृषक समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी

केके अग्रवाल, रामकिशन पटेल,

वही के पंड्या, संजय जैन और

प्रतीक जैन मौजूद रहे।

न्यूज गैलरी

एमपीडब्ल्यू को पूरे सेवा काल में नहीं मिलेगी पदोन्नति

जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने जबलपुर लोकसभा सांसद आशीष दुवे को ज्ञान सौपकर बताया कि प्रदेश में पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ लगातार छत्तावा हो रहा है। शासन द्वारा 1484 सुपरवाईजर के पदों को डाईंग केंद्र घोषित कर दिया गया है, जबकि सुपरवाईजर कार्यरत हैं, यह नियम विरुद्ध है। एमपीडब्ल्यू का प्रमोशन सुपरवाईजर के पद पर होता है परंतु सुपरवाईजर का पद डाईंग केंद्र होने के कारण अधिकारियों द्वारा उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही है, जिससे एमपीडब्ल्यू जीवन भर एक ही पद पर कार्य करता रहेगा उसे किसी भी प्रकार की पदोन्नति नहीं मिल पायेगी। इसके साथ ही एमपीडब्ल्यू/एनएम को समयमान वेतनमान में भी विसंगति शासन द्वारा की गई है। समयमान का मूलउद्देश्य उच्च पद का वेतनमान देना है परंतु वित्त विभाग द्वारा उच्च पदों का वेतनमान न देते हुए एमपीडब्ल्यू के लिए अलग से ही समयमान सारणी जारी कर दी गई है जो उच्च पदों के वेतनमान से अत्यंत कम है।

14वें दिन भी जारी रहा रादुविवि कर्मचारी संघ का क्रमिक अनशन

जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का 36 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक अनशन बुधवार को 14वें दिन भी जारी रहा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के पदाधिकारियों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया। परिषद के कर्मचारियों की पदोन्नति, समयमान वेतनमान, वार्षिक वेतनवृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। कर्मचारी संघ अध्यक्ष संजय यादव ने विश्वविद्यालय में कथित प्रशासनिक अव्यवस्था और कार्यप्रणाली से कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष का आरोप लगाते हुए 36 सूत्रीय मांगों के समयबद्ध निराकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि मांगों पर ठोस पहल नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। परिषद के पदाधिकारियों ने भी शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की।

कूलर के करंट ने ली युवती की जान

जबलपुर। गोसलपुर थाना अंतर्गत गांधीग्राम में कल देर रात कूलर में करंट उतरने से 19 वर्षीय युवती अंजलि असाठी की मौत हो गई। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, अंजलि असाठी अपने बिस्तर पर सो रही थी। ठंड लगने पर वह चादर लेने के लिए उठी। इसी दौरान कमरे में लगे कूलर के पास से गुजरते समय वह अचानक उसमें फैले करंट की चोट में आ गई, और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सिहोरा में नाबालिग फांसी पर लटका

जबलपुर। सिहोरा थाना क्षेत्र के ईमलहा मोहल्ले में रात शाम 17 वर्षीय किशोर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे नीचे उतारकर शासकीय सिविल अस्पताल सिहोरा ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 9 निवासी नरेश उर्फ निहाल के रूप में हुई है। उसके पिता गणेश कोल भोपाल में काम करते हैं, घर पर मां माया बाई थी. आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है. सिहोरा पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है. बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया।

गंटे पेयजल की सप्लाई पर आज महापौर से मिलेंगे जनसंगठन

जबलपुर। जबलपुर। शहर में मरीजों की बढ़ती संख्या और पाइपलाइनों में लीकेज के कारण पेयजल में गंदा पानी मिलने की समस्या को लेकर विभिन्न नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि आज गुरुवार दोपहर 12 बजे महापौर जगत बहादुर सिंह अत्रू से मुलाकात करेंगे। नागरिक उपभोक्ता माहोदशक मंच, भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन और पेंशनर्स समाज के प्रतिनिधि महापौर के समक्ष पेयजल की गुणवत्ता सहित नागरिकों से जुड़ी समस्याएं रखेंगे।

रिछाई की 35 एकड़ भूमी पर बनाया जाए टेलीकाम हब

जबलपुर। टेलीकॉम क्लस्टर तथा मैनुफैक्चरिंग स्मि्ट जबलपुर में बनना यह जबलपुर का हक है, इससे जबलपुर का टेलीकॉम हब मजबूत होगा, साथ ही अनेकों बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इस टेलीकॉम क्लस्टर को रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में बनाने से टेलीकॉम रिछाई की x5 एकड़ खाली पड़ी भूमि का भी उपयोग हो जायेगा। जब केन्द्र सक्षम 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है तो जबलपुर के इस टेलीकॉम क्लस्टर का भी एमओयू किया जा सकता है।

अवैध कॉलोनी के निर्माणकर्ताओं नगर निगम की कार्रवाई

जबलपुर। नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण और शासकीय भूमि पर कब्जे के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम की कॉलोनी सेल एवं अतिक्रमण दस्ते ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 900 वर्गमीटर बेशकीमती शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त कराया है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 65 लाख रुपये है। कॉलोनी सेल प्रभारी सुनील दुवे ने बताया कि वार्ड क्रमांक 16 महाणगा प्रताप वाड़, मौजा परलवाड़ा स्थित खसरा नंबर 118/1/1 एवं 118/1/2 की भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी तथा उसके पहुंच मार्ग के लिए शासकीय खसरा नंबर 118/2 की भूमि पर अनधिकृत निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनी के निर्माणकर्ताओं घ्रव भोला एवं रूपेश तिवारी को पूर्व में नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वैधानिक स्वीकृत दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर प्रशासन ने निष्पक्ष रूप से मार्ग व अवैध ढांचे को हटाने की कार्रवाई की। कार्यवाही के दौरान अपराधुक्त सौरभ मिश्रा,कॉलोनी सेल प्रभारी सुनील दुवे, सहायक अतिक्रमण अधिकारी दीपेंद्र रावत, मनोज तिवारी एवं कॉलोनी सेल की टीम तथा अतिक्रमण शाखा कर्मचारी उपस्थित रहे।

युवा कूटनीति से मजबूत हो रहे भारत-वियतनाम संबंध

नवप्रदेश/जबलपुर। एनसीसी के भारत-वियतनाम युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत भारतीय कैडेटों ने हनोई और न्हा ट्रंग में विभिन्न सैन्य, शैक्षणिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कर दोनों देशों के बीच युवा संपर्क को मजबूत किया। 10 अगस्त से शुरू हुए कार्यक्रम में 4 एमपी सीटीआर, एनसीसी जबलपुर की लेफ्टिनेंट कर्नल अमृता सिंह ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी, एयर फोर्स ऑफिसर कॉलेज, खान होआ प्रांतीय युवा संघ सहित विभिन्न संस्थानों में संवाद और कार्य सत्र हुए। कैडेटों ने स्थानीय उद्योगों और सांस्कृतिक स्थलों का भी अवलोकन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अमृता सिंह ने वियतनाम में भारत के राजदूत लौरिंग वांन्चुक शेरेपा से मुलाकात की। न्हा ट्रंग में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम ने कैडेटों में नेतृत्व, सांस्कृतिक समझ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव विकसित किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने की कार्यवाही जारी



जबलपुर। दूधित और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय पर सख्ती से लगाम लगाने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की आकस्मिक जांच की कार्यवाही बुधवार को भी जारी रही। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ बुधवार को कटंगी में तीन खाद्य प्रतिष्ठिों का आकस्मिक निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने बताया कि कटंगी स्थित अभिषेक खोवा भंडार से खोवा, झुरे के रसगुल्ल से खोवा एवं रसगुल्ल तथा सलैया नमकीन से बेसन एवं नमकीन के सैंपल लिये। इसी प्रकार राजस्व अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जबलपुर में नौदरा फ्रिज स्थित मनोहर स्वीट से पेड्ड, गोरखपुर स्थित उमेश डेरी से घी एवं पनीर तथा गोरखपुर में ही नरेंद्र डेयरी से खोवा एवं पनीर के सैंपल लिए गए। सभी नमूने परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

तीन माह से वेतन के इंतजार में सफाई मित्र, कैसे सफल होगा स्वच्छ भारत मिशन?

डूमरकछार नगर परिषद में मई, जून और जुलाई का मानदेय लंबित, सफाई व्यवस्था पर पड़ने लगा असर



कारण घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां, बिजली-पानी के बिल और अन्य आवश्यक खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। **तीन माह से भुगतान लंबित, परिवारों पर बढ़ा आर्थिक दबाव:** सफाई कर्मचारियों के अनुसार, वे प्रतिदिन नगर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद मई, जून

और जुलाई माह का भुगतान लंबित है। कर्मचारियों का कहना है कि दैनिक वेतन पर निर्भर परिवारों के लिए लगातार तीन माह तक भुगतान नहीं मिलना बेहद कठिन स्थिति है। कर्मचारियों ने मांग की है कि लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान किया जाए और भविष्य में प्रत्येक माह निर्धारित समय पर वेतन उपलब्ध कराने की स्थायी व्यवस्था बनाई जाए।